नई दिल्ली
शनिवार
28 नवम्बर 2026
वर्षः 13, अंकः 85
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की



मलेशिया को 6-2 से हराकर फाइनल में पहुंचा...पेज-06

DELHIN/2014/58158

दिल्ली-बिहार के बीच 18 मार्गों पर अंतरराज्यीय बस...पेज-05

एक नजर

एमएलएफएफ टोल प्लाजा पर नंबर प्लेट छिपाने पर लगेगा पांच गुना जुर्माना

नई दिल्ली। मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोलिंग व्यवस्था वाले प्लाजा पर टोल शुल्क से बचने के लिए वाहन की नंबर प्लेट जानबूझकर छिपाने, उसमें छेड़छाड़ करने या फास्टैग नहीं लगाने पर अब संबंधित वाहन चालक से लागू टोल शुल्क का पांच गुना जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना टोल शुल्क की वसूली के अतिरिक्त होगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि एमएलएफएफ एक बैरियर रहित इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग व्यवस्था है। इसमें सड़क के ऊपर लगे गैंट्री पर फास्टैग रीडर और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) कैमरों के जरिए वाहनों की पहचान कर टोल शुल्क स्वतः काट लिया जाता है। इससे वाहनों को रुकना नहीं पड़ता और प्रतीक्षा समय, यातायात जाम, ईंधन की खपत तथा प्रदूषण में कमी आती है। मंत्रालय के अनुसार, यह जुर्माना उन मामलों में लागू होगा, जहां यह स्थापित हो कि वाहन चालक ने टोल शुल्क से बचने के इरादे से नंबर प्लेट को छिपाया, उसमें छेड़छाड़ की या उसे अस्पष्ट किया अथवा फास्टैग नहीं लगाया। इसमें वाहन की आगे या पीछे की नंबर प्लेट अथवा दोनों को छिपाने के मामले शामिल होंगे, जहां फास्टैग की भी पहचान नहीं हो सकी हो। जुर्माने की राशि संबंधित टोल प्लाजा पर लागू शुल्क की पांच गुना होगी। यह राशि प्राधिकरण को दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि दोषी वाहनों की पहचान मजबूत और तकनीक आधारित प्रक्रिया के जरिए की जाएगी। यह प्रावधान उन सभी स्थानों पर लागू होगा, जहां एमएलएफएफ व्यवस्था पहले से संचालित है। भविष्य में जिन नए स्थानों पर यह व्यवस्था शुरू की जाएगी, वहां भी यह लागू होगा।

ट्राई ने दूरसंचार अंतःसंयोजन नियमों में किया संशोधन, 1 जनवरी से होंगे लागू

नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों के बीच नेटवर्क अंतःसंयोजन से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत बाजार में पर्याप्त शक्ति रखने वाली कंपनियों के लिए संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) जमा करने और प्रकाशित करने की समय-सीमा तय की गई है। साथ ही, नेटवर्क रूटिंग व्यवस्था को आधुनिक बनाने और नियमों के उल्लंघन पर वित्तीय निरुत्साहन का प्रावधान किया गया है। संशोधित नियम 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। ट्राई ने शुक्रवार को 'दूरसंचार अंतःसंयोजन (संदर्भ अंतःसंयोजन प्रस्ताव) (संशोधन) विनियम, 2026' जारी किए। इनका उद्देश्य मौजूदा लाइसेंस और प्राधिकरण व्यवस्था के अनुरूप अंतःसंयोजन ढांचे को आधुनिक बनाना तथा सेवा प्रदाताओं के बीच पारदर्शिता, गैर-भेदभाव और प्रभावी नेटवर्क संपर्क सुनिश्चित करना है। नए नियमों के अनुसार, किसी लाइसेंस प्राप्त या प्राधिकृत दूरसंचार सेवा क्षेत्र में यदि किसी सेवा प्रदाता की निर्धारित मानदंडों में हिस्सेदारी 30 प्रतिशत या उससे अधिक है तो उसे बाजार में पर्याप्त शक्ति (एसएमपी) वाला माना जाएगा। इसके लिए समायोजित सकल राजस्व, उपभोक्ता आधार, नेटवर्क की ध्वनि कॉल प्रबंधन क्षमता और ट्रैफिक का परिमाण आधार होंगे। ट्राई प्रत्येक सेवा क्षेत्र में इन मानदंडों के आधार पर एसएमपी की स्थिति का निर्धारण करेगा।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परिसीमन संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

नई दिल्ली,एजेंसी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने परिसीमन संशोधन विधेयक और इससे संबंधित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सेवा तीर्थ में हुई बैठक में इन विधेयकों को मंजूरी दी गई। यह माना जा रहा है कि सरकार इन विधेयकों को 30 नवम्बर से बुलाई गई संसद की बैठक में पेश करने वाली है। परिसीमन विधेयक में सभी राज्यों में अनुपात के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढाने का प्रस्ताव है। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में सीटों की यह संख्या अगले 25 वर्षों तक फ्रीज रहेगी। परिसीमन विधेयक के आधार पर ही लोकसभा में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि बैठक में सरकार सदन की स्वीकृति के लिए अति महत्वपूर्ण कामकाज लायेगी।

उन्होंने सभी सांसदों से चर्चा में गंभीरता से भाग लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर और एक दिसंबर को लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण 'बिजनेस' लाया जायेगा और उसे ही दो और तीन दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया जायेगा। उन्होंने इस संबंध में किसी विधेयक का नाम नहीं लिया और कहा कि कामकाज क्या होगा इसकी जानकारी उचित समय पर दे दी जायेगी। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय ने संसद की इस बैठक को मानसून सत्र का दूसरा भाग बताया है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ था और 13 अगस्त को दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी लेकिन अभी तक औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया था। इस तरह दोनों सदनों की ये बैठकें मानसून सत्र का ही विस्तार होंगी। आमतौर पर मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए



जाने के कुछ दिन बाद सत्रावसान कर दिया जाता है और नवम्बर के अंतिम सप्ताह में शीतकालीन सत्र बुलाया जाता है। सत्रावसान करने के बाद नए सत्र के लिए राष्ट्रपति से अनुमति ली जाती है लेकिन इस बार मानूसन सत्र का सत्रावसान न किए जाने की वजह से राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं है। विपक्ष मानसून सत्र का सत्रावसान न किए जाने को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल उठाता रहा है और इसे संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करार देता रहा है।

विपक्षी दलों विशेष रूप से कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय लोकतंत्र में भरोसा नहीं है। विपक्ष लगातार यह भी कहता रहा है कि सरकार परिसीमन विधेयक तथा महिला आरक्षण संबंधी विधेयक को जोड़ तोड़ से पारित कराने के लिए अचानक संसद की बैठक बुलाना चाहती है इसीलिए मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किया जा रहा है। सरकार गत अप्रैल में परिसीमन विधेयक लोकसभा में लाई थी लेकिन विपक्ष की एकजुटता के कारण मतविभाजन में यह विधेयक गिर गया था। संविधान संशोधन विधेयक होने के कारण इसे पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत की जरूरत है। इस बीच सरकार इन विधेयकों को पारित कराने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से परोक्ष रूप से बातचीत करती रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा कई अन्य मंत्री लगातार यह कहते रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार महिला आरक्षण विधेयक पारित अवश्य कराएगी।

कैंसर के इलाज और शोध को बेहतर बनाने के लिए सामूहिक राष्ट्रीय प्रयास जरूरीः उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली,एजेंसी। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार को कैंसर के उपचार और इससे जुड़े शोध को बेहतर बनाने के लिए देशभर के अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों के बीच सामूहिक प्रयासों तथा सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा अनुसंधान और नई खोजों का लाभ पूरी मानवता तक पहुंचना चाहिए, न कि इसे कुछ देशों या विशेष वर्गों तक सीमित रखा जाना चाहिए। राधाकृष्णन ने यहां ओखला स्थित होली फैमिली अस्पताल के नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। इस अवसर पर उन्होंने 'होली फैमिली अस्पताल स्मारिका 2026' का विमोचन किया और नए ब्लॉक के निर्माण में योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया।

उपराष्ट्रपति ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करते हुए देशभर के कैंसर अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को एक साझा मंच पर लाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे विभिन्न संस्थान अपने शोध, अनुभव, ज्ञान और उपचार के बेहतर तरीकों को एक-दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे। उन्होंने इस दिशा में सहयोग को मजबूत करने के लिए पहल की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ करुणामय, मानवीय और किफायती उपचार सुनिश्चित करना चाहिए। नए सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक से विशेष चिकित्सा सुविधाओं तक लोगों की पहुंच बढ़ेगी लेकिन ऐसी सुविधाओं की वास्तविक सफलता इस बात पर



निर्भर करेगी कि उन्नत उपचार कितनी किफायती दरों पर और कितनी मानवीय संवेदना के साथ उपलब्ध कराया जाता है। राधाकृष्णन ने कहा कि किसी अस्पताल की वास्तविक शक्ति केवल उसके बुनियादी ढांचे और आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से नहीं बल्कि वहां काम करने वाले चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के समर्पण, विशेषज्ञता तथा मानवीय संवेदना से तय होती है। होली फैमिली अस्पताल की विरासत का उल्लेख करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1953 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस अस्पताल की आधारशिला रखी थी। यह निरंतरता दर्शाती है कि जनसेवा के संकल्प के साथ स्थापित संस्थान पीढ़ियों तक समाज को लाभ पहुंचाते हैं। अस्पताल की ओर से जाति, धर्म और आर्थिक स्थिति के भेदभाव के बिना सभी को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की बुनियाद आपसी सम्मान और प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता पर टिकी है। अच्छे कार्यों और निःस्वार्थ सेवा को हमेशा प्रोत्साहित और सम्मानित किया जाना चाहिए।

मानव सेवा ही सच्ची आध्यात्मिकता हैः राजनाथ

बेंगलुरु,एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल पूजा-अर्चना तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करना ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। राजनाथ सिंह शुक्रवार को बेंगलुरु में बीजीएस एवं एसजेबी समूह के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि श्रीआदिचुंचनगिरि मठ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहा है। मठ के प्रयासों से हजारों लोगों के जीवन में आशा और सहयोग का संचार हो रहा है। मठ के कार्य 'मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है' की भावना को साकार करते हैं।

उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता हमें स्वयं को समझने, अपने मूल्यों के प्रति दृढ़ रहने और बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। यह हमें अपनी जिम्मेदारियों से दूर नहीं करती बल्कि उन्हें अधिक उद्देश्यपूर्ण और संवेदनशील तरीके से निभाने की



प्रेरणा देती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार अधिक सुलभ और किफायती बन रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, सस्ती दवाओं की उपलब्धता, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और बेहतर उपचार सुविधाओं के विकास से आम लोगों को लाभ मिल रहा है। आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्रों जैसी पहलों के माध्यम से देशभर में करोड़ों लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब उन्नत स्वास्थ्य तकनीकों को अपनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका स्वदेशी विकास भी कर रहा है।

संसद की बैठक में होगा अति महत्वपूर्ण कामकाजः रिजिजू

नई दिल्ली। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि संसद की 30 नवंबर से होने वाली बैठक में सरकार सदन की स्वीकृति के लिए की अति महत्वपूर्ण कामकाज लायेगी। उन्होंने सभी सांसदों से चर्चा में गंभीरता से भाग लेने का अनुरोध किया। श्री रिजिजू ने कहा कि 30 नवंबर और एक दिसंबर को लोकसभा में बहुत ही महत्वपूर्ण 'बिजनेस' लाया जायेगा और उसे ही दो और तीन दिसंबर को राज्यसभा में पेश किया जायेगा। उन्होंने इस संबंध में किसी विधेयक का नाम नहीं लिया और कहा कि कामकाज क्या होगा इसकी जानकारी उचित समय पर दे दी जायेगी। संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ सांसदों का यह कहना अनुचित है कि सरकार सत्र के मामले में संसदीय परंपराओं के अनुसार काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी किसी एक सत्र का सत्रावसान किये बिना फिर से संसद की बैठक बुलाये जाने के उदाहरण हैं।

नायडू ने लोस की मौजूदा 543 सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर विस्तारित सदन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की वकालत की

नई दिल्ली,एजेंसी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर विस्तारित सदन में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सकेगा और परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों में जताई जा रही आशंकाओं का भी समाधान हो सकता है। नायडू ने परिसीमन का विरोध कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों से सवाल किया कि आखिर उनके पास महिला आरक्षण लागू करने का क्या विकल्प है?

नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायडू ने कहा कि विपक्ष को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दक्षिणी राज्यों के राजनीतिक हितों को प्रभावित किए बिना महिलाओं को उनका अधिकार कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की मौजूदा सीटों पर ही 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने से पुरुषों के



प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में कुल सीटों में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर महिला आरक्षण लागू करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से लंबित है और अब इसे लागू करने का समय आ गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों की सराहना करते हुए सभी राजनीतिक दलों से इस ऐतिहासिक पहल पर सहमति बनाने की अपील की। नायडू ने सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण के समर्थन में स्पष्ट और एकजुट रुख अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि संसद में पहले इस मुद्दे पर आई बाधाओं और प्रक्रियागत देरी से सबक लेते हुए राजनीतिक दलों को पुरानी गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। महिलाओं की लंबे समय से चली आ रही जायज मांग को अब हकीकत में बदलने का अवसर है।

भारतीय निर्यातकों से अधिक भागीदार देश उठा रहे एफटीए का लाभः आरबीआई गवर्नर

नई दिल्ली/मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने वाले देश इन समझौतों का लाभ भारतीय निर्यातकों की तुलना में कहीं बेहतर तरीके से उठा रहे हैं। उन्होंने भारतीय कंपनियों से इन समझौतों का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। संजय मल्होत्रा ने मुंबई में एसएमई चैंबर ऑफ इंडिया के 33वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एसएमई वित्त और निवेश शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस शिखर सम्मेलन में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने



अपने संबोधन में एमएसएमई क्षेत्र के वित्तपोषण, विस्तार तथा नवाचार पर जोर दिया है।

मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू निर्यातक एफटीए का 'बहुत कम' इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के तहत कम शुल्क का लाभ उठाने के पात्र भारतीय निर्यातकों में से केवल 20-30 फीसदी ही इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई एक लचीली और समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक हैं। मल्होत्रा ने कहा कि घरेलू निर्यातक एफटीए का 'बहुत कम' इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के तहत कम शुल्क का लाभ उठाने के पात्र भारतीय निर्यातकों में से केवल 20-30 प्रतिशत ही इसका फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा, ''भारत को निर्यात करने वाले भागीदार देशों के 60-70 फीसदी निर्यातक इन समझौतों का लाभ उठा रहे हैं, जबकि भारत में इनका इस्तेमाल बेहद कम है। इस तरह हम एक बड़े अवसर का लाभ उठाने से चूक रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कारोबारियों से मिलना महत्वपूर्ण है और उनकी मंशा पर संदेह नहीं करना चाहिए।

मनुष्यता की अभिव्यक्ति करुणा बिना संभव नहीं: मोहन भागवत

नई दिल्ली,एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने शुक्रवार को यहां भगवान राम पर लिखी पुस्तक के विमोचन समारोह में कहा कि मनुष्यता की अभिव्यक्ति करुणा से होती है और भगवान राम के चरित्र में इसका प्रगटीकरण है। करुणा सत्य को समझने की नीति है। सत्य यह है कि हम सब एक ही की अभिव्यक्ति हैं। इस सत्य को समझना और उसकी अभिव्यक्ति में लाना ही करुणा है।

संघ प्रमुख भागवत ने अंबेडकर भवन में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी की पुस्तक 'करुणानायक' का विमोचन किया। इस अवसर पर उनके साथ भूटान की राजकुमारी देचन वांगचुक, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संस्कृति मंत्रालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय



कला केंद्र और प्रभात प्रकाशन की ओर से आयोजित किया गया था। पुस्तक का प्रकाशन प्रभात प्रकाशन ने किया है।

सरसंघचालक ने संघ के स्वयंसेवकों का उदाहरण दिया और कहा कि स्वयंसेवक समाज के दुख को दूर करने की प्रेरणा से कार्यकर्ता है। दुनिया में भय, स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित होकर भी सेवा कार्य किए जाते हैं लेकिन अपनेपन की अनुभूति ही वह प्रेरणा है जिससे सेवाकार्य निरंतर जारी रहता है और इसी का नाम करुणा है। संघ का स्वयंसेवक भी इसी प्रेरणा से कार्य कर रहा है। लेखन कार्य की प्रशंसा करते हुए डॉ. भागवत ने कहा कि वैश्विक संघर्षों के बीच इस पुस्तक का आना नियति का ही कोई रूप है। दुनिया असल में मैं और मेरा के लिए लड़ रही है। करुणा में इसका अभाव होता और संघर्ष नहीं होता। यही बात विश्व को भारत ने समझाने का प्रयास किया है। मनुष्यता की अभिव्यक्ति करुणा से होती है। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि राम को समझना भारत को समझने और भारत को समझना राम को समझने जैसा है। करुणा राम के गुणों में कौस्तुभ मणि के समान है। उन्होंने कहा कि कृतज्ञता भाव करुणा के बिना संभव नहीं है। राजकुमारी वांगचुक ने कहा कि भूटान की संस्कृति में करुणा को बहुत महत्व दिया जाता है। इसी कारण से हमारे यहां मनुष्य की प्रगति को उसके बेहतर और खुशनुमा जीवन से आंका जाता है। उन्होंने कहा कि करुणा असल में हमारे चरित्र का साहस है। उन्होंने आशा व्यक्त की की यह पुस्तक युवाओं को प्रेरित करेगी। कैलाश सत्यार्थी ने पुस्तक लिखने के अपने अनुभव साझा किये। उन्होंने कहा कि राम और रावण का अंतर ही यही था कि राम करुणामय थे और रावण करुणा रहित था।

दिल्ली की सफाई व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार, 70 आधुनिक मशीनों से रोजाना 5,000 किलोमीटर सड़कों की होगी सफाई

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली! दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और सड़क की धूल पर नियंत्रण पाने के लिए दिल्ली सरकार और नगर निगम ने सफाई व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने शुक्रवार, 27 नवंबर 2026 को डॉ. एस.पी.एम. सिविक सेंटर स्थित दिल्ली नगर निगम मुख्यालय से 10 नई मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों (एमआरएसएम) एवं 9 सहायक वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।



इस पहल के तहत दिल्ली नगर निगम के बेड़े में कुल 70 आधुनिक मशीनें शामिल की जाएंगी। इसके बाद निगम के पास मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों की संख्या 66 से बढ़कर 136 हो जाएगी। इससे प्रतिदिन लगभग 5,000 किलोमीटर सड़क की लेन लंबाई की यांत्रिक सफाई का लक्ष्य पूरा किया जा सकेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी को लंबे समय से आधुनिक सफाई व्यवस्था की आवश्यकता थी। 70 आधुनिक मशीनों का शामिल होना दिल्ली की सफाई व्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पहले चरण में 10 मशीनें पहुंच चुकी हैं और शेष 60 मशीनें भी जल्द ही निगम के बेड़े में शामिल की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि नई मशीनें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), सेंसर और आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम से लैस हैं। इनके जरिए कंट्रोल रूम से मशीनों की आवाजाही, तय की गई दूरी, काम के घंटे और एकत्रित धूल की मात्रा पर नजर रखी जा सकेगी। इससे सफाई कार्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावशीलता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण सड़क की धूल है। खासकर सर्दियों के मौसम में इसका प्रभाव अधिक दिखाई देता है। ऐसे में आधुनिक मशीनों के माध्यम से धूल को नियंत्रित करना प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 10 नई मशीनों के साथ 9 सहायक वाहन भी रवाना किए गए हैं। इनमें 5 वाटर टैंकर और 4 डस्ट डंप वाहन शामिल हैं। ये वाहन सड़कों से एकत्रित धूल एवं कचरे को हटाने और पानी के छिड़काव के साथ सफाई व्यवस्था को प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। मशीनों के रखरखाव के लिए टेंडर में 10 वर्षों की व्यवस्था भी की गई है।

दिल्ली के महापौर श्री प्रवेश वाही ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली नगर निगम प्रदूषण के खिलाफ लगातार काम कर रहा है। निगम अपने संसाधनों को बढ़ाने के साथ सफाई व्यवस्था को आधुनिक और मशीनीकृत बनाने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनों की तैनाती से सड़क सफाई में तेजी आएगी और धूल नियंत्रण के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। निगम का उद्देश्य दिल्लीवासियों को स्वच्छ और बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राजधानी में धूल प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीक आधारित उपाय अपनाए जा रहे हैं। नई मशीनें सीएनजी और बिजली से संचालित होंगी, जिससे प्रमुख मार्गों पर सफाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य आधुनिक तकनीक, बेहतर निगरानी और प्रभावी सफाई व्यवस्था के माध्यम से सड़क की धूल को नियंत्रित करना और दिल्ली को स्वच्छ एवं प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में लगातार काम करना है। 66 से बढ़कर 136 होगी मशीनों की संख्या, दिल्ली नगर निगम के पास वर्तमान में 66 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें हैं, जो प्रतिदिन आठ घंटे की एक शिफ्ट में लगभग 2,100 किलोमीटर सड़क की लेन लंबाई की सफाई करती हैं। नई परियोजना के अंतर्गत 70 अतिरिक्त मशीनें शामिल की जाएंगी। इनमें 55 इलेक्ट्रिक मशीनें और 15 सीएनजी संचालित मशीनें होंगी। इलेक्ट्रिक मशीनों की हॉपर क्षमता 2 घन मीटर और सीएनजी मशीनों की क्षमता 4 घन मीटर से अधिक होगी। प्रत्येक नई मशीन से एक शिफ्ट में प्रतिदिन न्यूनतम 40 किलोमीटर सड़क की लेन लंबाई की सफाई सुनिश्चित की जाएगी। सभी 70 मशीनें शामिल होने के बाद प्रतिदिन लगभग 5,000 किलोमीटर सड़क की लेन लंबाई की यांत्रिक सफाई संभव हो सकेगी। शेष मशीनों को चरणबद्ध तरीके से दिल्ली नगर निगम के सभी 12 जोनों में तैनात किया जाएगा। इस कार्यक्रम में महापौर प्रवेश वाही, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, स्थायी समिति अध्यक्ष सत्या शर्मा, निगम आयुक्त संजीव खिरवार, वरिष्ठ निगम पार्षदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।

दिल्ली विस में 'संविधान के नायक' नामक नाट्य प्रस्तुति का आयोजन

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। भारत के संविधान अंगीकरण की 77वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में दिल्ली विधानसभा द्वारा आज 'संविधान के नायक' नामक नाट्य प्रस्तुति का आयोजन किया गया। शुक्रवार की शाम विधानसभा परिसर में रस कला मंच द्वारा इस नाटक का मंचन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने की। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मुख्य अतिथि तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस नाटक ने संविधान सभा की बहसों और विचार-विमर्श को वर्तमान से जोड़कर हमारे सामने जीवंत कर दिया। संग्रहालय में रात के अंधेरे में जब वहाँ स्थापित प्रतिमाएँ जीवंत हुईं, तो हम संविधान के उन अनुच्छेदों के निर्माण के पीछे हुई चर्चाओं और आज के संदर्भ में उनके महत्व को समझ सके, जिन्हें हम आज पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संविधान सभा ने दो वर्ष, ग्यारह महीने और अठारह दिनों की अवधि में कुल 165 बैठकें कीं। हमारा संविधान इसी सतत प्रयास, गहन अध्ययन और व्यापक विचार-विमर्श का परिणाम है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारतीय संविधान के बिना भारत की कल्पना करना असंभव है। 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे देश में, जहां अनेक राज्य, भाषाएं, बोलियां, परंपराएं और संस्कृतियां हैं, वहां संविधान ही वह सूत्र है जो हम सभी को एकता के बंधन में बांधकर रखता है।

इस अवसर पर संविधान निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों के योगदान तथा उनके विचार-विमर्श को दिशा देने वाले लोकतांत्रिक सिद्धांतों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक अभय वर्मा तथा अन्य विधायक भी उपस्थित रहे। रवि मोहन द्वारा परिकल्पित एवं निर्देशित 'संविधान के नायक' नाटक की शुरुआत अगस्त 1947 में स्वतंत्रता की ऐतिहासिक मध्यरात्रि से होती है और यह भारत की यात्रा को वर्तमान समय तक प्रस्तुत करता है। संविधान संग्रहालय की पृष्ठभूमि पर आधारित इस नाटक में डॉ. बीआर आंबेडकर, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे महान राष्ट्रनिर्माताओं के चरित्रों को मंच पर जीवंत किया गया। इन महान विभूतियों के माध्यम से नाटक में सामाजिक असमानता, भ्रष्टाचार तथा मौलिक अधिकारों और नागरिक कर्तव्यों के बीच संबंध जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया।

बैलेट पेपर पर जेन-जी का जनादेश, राष्ट्रविरोधी विमर्श को करारा जवाब : डॉ वीरेंद्र सोलंकी

नई दिल्ली/गोवा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) के राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने शुक्रवार को कहा कि यह विजय स्पष्ट करती है कि जेन-जी नकारात्मकता और अराजकता के बजाय राष्ट्रहित, लोकतांत्रिक मूल्यों और विद्यार्थियों के वास्तविक मुद्दों को प्राथमिकता देने वाली छात्र राजनीति के साथ खड़ी है। गोवा विश्वविद्यालय छात्र परिषद के शैक्षणिक सत्र 2026-27 के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त करते हुए सभी 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। बैलेट पेपर के माध्यम से संपन्न हुए इन चुनावों में विद्यार्थियों ने अभाविप के नेतृत्व, विचारधारा और छात्रहितों के प्रति उसकी प्रतिबद्धता पर विश्वास जताया। अभाविप ने अध्यक्ष, सचिव, महिला सदस्य सहित सभी छह कार्यकारी सदस्यों के पदों पर विजय प्राप्त कर छात्र परिषद में अपना पूर्ण बहुमत स्थापित किया है।

सोलंकी ने इस ऐतिहासिक विजय पर सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों एवं अभाविप के सदस्यों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए कहा 'गोवा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने बैलेट पेपर के माध्यम से अपना स्पष्ट जनादेश देकर राष्ट्रविरोधी विमर्श और शैक्षणिक परिसरों में अराजकता का वातावरण बनाने वाली ताकतों को करारा जवाब दिया है। पिछले कुछ समय से देशभर में शैक्षणिक परिसरों की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने तथा विद्यार्थियों के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अभाविप ने ऐसे प्रयासों के विरोध में देशभर में प्रदर्शन कर लोकतांत्रिक छात्र व्यवस्थाओं की मजबूती और परिसरों में सकारात्मक वातावरण की स्थापना के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। अभाविप सदैव विद्यार्थियों की शैक्षणिक समस्याओं, परिसर की व्यवस्थाओं, छात्र सुविधाओं एवं उनके अधिकारों से जुड़े विषयों को प्रमुखता से उठाती रही है। गोवा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने जनादेश के माध्यम से अभाविप के इन्हीं छात्रहितकारी प्रयासों, राष्ट्रहित के प्रति प्रतिबद्धता और सकारात्मक छात्र राजनीति पर अपना विश्वास व्यक्त किया है। अभाविप कोंकण प्रांत के प्रांत मंत्री राहुल रजोरिया ने भी इस विजय पर सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि गोवा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने अभाविप के छात्रहितकारी कार्यों और सकारात्मक नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त किया है। यह विजय अभाविप के सदस्यों के निरंतर परिश्रम तथा विद्यार्थियों के साथ उनके सतत संवाद का परिणाम है। नवनिर्वाचित छात्र परिषद विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान, शैक्षणिक वातावरण को बेहतर बनाने तथा परिसर में रचनात्मक एवं लोकतांत्रिक छात्र गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी।

संविधान दिवस पर दिल्ली कांग्रेस की संविधान रक्षा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, भाजपा सरकार के खिलाफ बुलंद हुई आवाज

सद्भावना टुडे, वरिष्ठ संवाददाता

नई दिल्ली। संविधान दिवस के अवसर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत आयोजित संविधान रक्षा यात्रा में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। चंदगी राम अखाड़े से डॉ. भीमराव आंबेडकर स्मारक तक निकाली गई इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार और चुनाव आयोग की कथित कार्यप्रणाली के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने संविधान, लोकतंत्र और नागरिकों के मताधिकार की रक्षा को लेकर अपना संकल्प दोहराया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर देशभर में कांग्रेस पार्टी संविधान रक्षा मार्च निकाल रही है। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने प्रत्येक नागरिक को समान मताधिकार दिया था और कांग्रेस इस अधिकार की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ संघर्ष करती रहेगी।

वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान के अनुरूप मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है, लेकिन आयोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार देशवासियों के वोट के अधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने के आरोप सामने आए हैं। लोकतंत्र में अमीर और गरीब सभी नागरिकों के वोट का समान महत्व है। किसी भी सरकार की सत्ता संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। उन्होंने



मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा।

दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि संविधान दिवस पर संविधान रक्षा यात्रा में हजारों लोगों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि देश के नागरिक संविधान, लोकतंत्र और अपने मताधिकार को लेकर जागरूक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की नीतियों और चुनाव आयोग की कथित पक्षपातपूर्ण कार्यप्रणाली के कारण लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है।देवेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक वोट का अधिकार देता है। जाति, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति या सामाजिक पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो, प्रत्येक भारतीय नागरिक लोकतंत्र में बराबर का हिस्सेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब एक ही व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में 10 से 15 बार दिखाई देता है और दूसरी ओर वैध मतदाताओं के नाम काट दिए जाते हैं, तो यह मताधिकार की भावना पर गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता 13 हजार से अधिक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी का उद्देश्य प्रत्येक दिल्लीवासी का वोट सुरक्षित और सुनिश्चित करना है। जब तक मतदाता सूची से जुड़े कथित अनियमितताओं के मामलों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक कांग्रेस का 'वोट बचाओ, देश बचाओ' आंदोलन जारी रहेगा। संविधान रक्षा यात्रा में युवाओं, छात्रों, महिलाओं, दलितों, मजदूरों, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और विभिन्न पेशों से जुड़े लोगों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। यात्रा शुरू होने से पहले केसी वेणुगोपाल और देवेंद्र यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संविधान रक्षा की शपथ दिलाई। देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार विपक्ष की लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 1 नवंबर 2026 को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित महारैली की सफलता के बाद भाजपा सरकार विपक्ष की आवाज से घबराई हुई है। कांग्रेस संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रहेगी।

दिल्ली नगर निगम में 2,500 अवकाशकालीन वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों की होगी भर्ती: महापौर



शबाना बेगम, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। सदभावना टुडे, दिल्ली नगर निगम राजधानी की सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 2,500 अवकाशकालीन वैकल्पिक सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने जा रहा है। दिल्ली के महापौर श्री प्रवेश वाही ने 27 नवंबर को निगम मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान यह महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों की नियुक्ति से दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और नियमित सफाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रेस वार्ता में स्थायी समिति की अध्यक्ष श्रीमती सत्या शर्मा तथा नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक एवं संबद्ध समिति के अध्यक्ष श्री मुकेश गोयल भी उपस्थित रहे। महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के लिए जल्द ही समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन जारी किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार संपन्न होगी। भर्ती प्रक्रिया की निगरानी के लिए उपायुक्त स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में तीन अलग-अलग टीमों का गठन किया जाएगा। ये टीमें आवेदन पत्रों की प्राप्ति, आवेदनों की जांच और अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण की प्रक्रिया पर नजर रखेंगी।

महापौर ने बताया कि भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ पिछले पांच वर्षों से दिल्ली में निवास करने का प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा आवेदक का संबंधित जोन के अधिकार क्षेत्र में रहना भी जरूरी होगा। निगम का कहना है कि इससे चयनित कर्मचारियों को अपने निर्धारित कार्यस्थल तक पहुंचने में सुविधा होगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदन पत्र पूरी तरह नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि आर्थिक तंगी के कारण कोई भी पात्र अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित न रहे। प्रेस वार्ता के दौरान महापौर ने निगम की कर्मचारी कल्याण संबंधी योजनाओं की जानकारी भी साझा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने करुणामूलक आधार पर नियुक्त 177 कर्मचारियों की सेवाओं को 1 अप्रैल 2004 से नियमित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में दिवंगत हुए निगम कर्मचारियों के 65 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर मल्टी टास्किंग स्टाफ (इंजीनियरिंग) के पद पर नियुक्ति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि दिल्ली नगर निगम राजधानी की स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भी लगातार प्रयासरत है। निगम का उद्देश्य कर्मचारियों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और दिल्लीवासियों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए सफाई कर्मचारियों की भर्ती से विभिन्न जोनों में सफाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर नगर सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

वीरेंद्र सहवाग ने शुरू किया 'शिखर ग्लोबल स्कॉलरशिप फंड', अपनी ओर से दिए 11 लाख रुपये

सद्भावना टुडे संवाददाता

नई दिल्ली। शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास और सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में पिछले 25 वर्षों से कार्यरत शिखर ऑर्गनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट (शिखर ह्यस्ष्ठ) ने अपनी सिल्वर जुबली के अवसर पर एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल की शुरुआत की। संगठन के 25वें वर्षगांठ समारोह में भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी एवं शिखर के मुख्य संरक्षक वीरेंद्र सहवाग ने 'शिखर ग्लोबल स्कॉलरशिप फंड' का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सहवाग ने स्वयं 11 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देकर जरूरतमंद और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने की पहल की। समारोह को संबोधित करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि वह शिखर संगठन से उसके शुरुआती दिनों से जुड़े हुए हैं और उन्होंने इसकी पूरी यात्रा को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि शिखर पूरी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण के साथ समाज की सेवा कर रहा है। संगठन के संस्थापक नसीम अख्तर और उनकी टीम ने पिछले 25 वर्षों में जिस निष्ठा के साथ काम किया है, वह सराहनीय है। सहवाग ने कहा कि इस स्कॉलरशिप फंड का उद्देश्य संगठन के अच्छे कार्यों को आने वाली पीढ़ियों तक जारी रखना है। उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, 'हम रहें या न रहें, लेकिन शिखर का नेक काम रुकना नहीं चाहिए।' उन्होंने देश के नागरिकों, कंपनियों, संस्थानों और सामाजिक संगठनों से इस फंड से जुड़ने तथा जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और उनके बेहतर भविष्य के निर्माण में सहयोग देने की अपील की।छात्रवृत्ति से शुरू हुआ था 25 वर्षों का सफर! शिखर ऑर्गनाइजेशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की स्थापना वर्ष 2001 में कुछ जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई थी। धीरे-धीरे संगठन ने शिक्षा के साथ महिला



सशक्तिकरण, युवा विकास, आजीविका, सामाजिक विकास और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) के क्षेत्र में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया। संगठन के अनुसार, पिछले 25 वर्षों में शिखर ने पांच राज्यों में विभिन्न सामाजिक एवं ष्टस्क परियोजनाओं को लागू किया है और इसकी अलग-अलग पहलों से 30 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है।

25 वर्षों की यात्रा पर विशेष मैगजीन का विमोचन

सिल्वर जुबली समारोह में शिखर की 25 वर्षों की उपलब्धियों, प्रमुख परियोजनाओं, लाभार्थियों की सफलता की कहानियों और सहयोगी संस्थानों के योगदान पर आधारित विशेष मैगजीन का भी विमोचन किया गया। वीरेंद्र सहवाग सहित समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने संयुक्त रूप से इसका विमोचन किया। इस अवसर पर संगठन के संस्थापक नसीम अख्तर ने 25 वर्षों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए सभी लाभार्थियों, ष्टस्क पार्टनर्स, सहयोगी संस्थानों, समर्थकों और टीम के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में शिक्षा, महिला एवं युवा सशक्तिकरण तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में संगठन अपने कार्यों को और व्यापक स्तर पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है।

अगले दस वर्षों का रोडमैप प्रस्तुत

समारोह में शिखर के अगले दस वर्षों की कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई। संगठन के मुख्य सलाहकार प्रो. आर. के. सूरी ने भविष्य की योजनाओं और अगले दशक के विजन की जानकारी दी। इस रोडमैप में शिक्षा एवं छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को मजबूत बनाने, महिला और युवा सशक्तिकरण की गतिविधियों का विस्तार करने, ष्टस्क के माध्यम से अधिक संस्थानों के साथ साझेदारी बढ़ाने तथा समुदायों के लिए टिकाऊ विकास मॉडल तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। 'शिखर ग्लोबल स्कॉलरशिप फंड' को इसी दीर्घकालिक योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया।

ममम 600 से अधिक लाभार्थियों और गणमान्य अतिथियों की भागीदारी

सिल्वर जुबली समारोह में आयकर विभाग के कमिश्नर अमिताभ शुक्ला (ड्डक्र), डॉ. पूरन चंद्र पांडेय, के.के. उपाध्याय, संचिता गैरोला, वर्धन त्रिवेदी, अभिषेक, आसिम अब्दुल्ला, अब्दुल कलाम तथा शिखर के अध्यक्ष इकराम खान सूरी सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 600 से अधिक लाभार्थियों और संगठन के सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान बच्चों एवं युवाओं ने विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर समारोह को यादगार बनाया। कार्यक्रम के अंत में शिखर के उपाध्यक्ष आदित्य घिल्डियाल ने सभी अतिथियों, सहयोगियों, लाभार्थियों और टीम सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त किया।

ममम सेवा के 25 वर्षों से भविष्य की नई उम्मीदों तक

शिखर की सिल्वर जुबली पर शुरू किया गया ग्लोबल स्कॉलरशिप फंड संगठन की सामाजिक प्रतिबद्धता को नई दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। वर्ष 2001 में जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के छोटे से प्रयास से शुरू हुई यह यात्रा आज शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, युवा विकास और सामाजिक उत्थान के व्यापक अभियान में बदल चुकी है। वीरेंद्र सहवाग की ओर से 11 लाख रुपये के योगदान के साथ शुरू हुई यह पहल जरूरतमंद और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने तथा समाज में शिक्षा के अवसरों को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 677 ग्राम ड्रग्स के साथ तस्कर गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपित की पहचान हरियाणा के जींद जिले के पिल्लूखेड़ा निवासी यश बिश्नोई (27) के रूप में हुई है। उसके कब्जे से 656 ग्राम अफीम और 21 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई है। बरामद मादक पदार्थों का कुल वजन 677 ग्राम है। क्राइम ब्रांच की एनआर-दो यूनिट को 25 नवंबर की शाम सूचना और गश्त के दौरान रोहिणी सेक्टर-34 स्थित यूईआर-दो सर्विस रोड पर एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। वह बवाना कैनाल ब्रिज की ओर से बैग लेकर आ रहा था। पुलिस टीम को देखकर वह भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके बैग से अफीम और एमडीएमए बरामद हुई। इस संबंध में क्राइम ब्रांच थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह 2016 से ट्रक चालक का काम कर रहा था। इसी दौरान उसे अफीम सेवन की लत लग गई। 2022 से वह बिहार के मुजफ्फरपुर से अफीम और एमडीएमए खरीदकर हरियाणा के जींद, रोहतक और दिल्ली से सटे सोनीपत के गांवों में सप्लाई करने लगा। पुलिस अब उसके ड्रग्स नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाने में जुटी है।

एक नजर

दिल्ली के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान को मकोका केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने दिल्ली के पूर्व विधायक नरेश बाल्यान की मकोका मामले में जमानत दे दी । जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया। न्यायालय ने 24 अगस्त को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 3 अगस्त को बाल्यान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।बाल्यान ने उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 5 मई 2025 को दिल्ली पुलिस की ओर से नरेश बाल्यान समेत पांच आरोपितों के खिलाफ दाखिल पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। उच्च न्यायालय में दिल्ली पुलिस ने नरेश बाल्यान की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि बाल्यान के खिलाफ मकोका का मामला बनता है क्योंकि 2019 के एफआईआर में आपराधिक मिलीभगत का खुलासा 2024 में हो गया। चार दिसंबर 2024 को वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को जमानत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मकोका के मामले में गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली पुलिस ने वसूली के मामले में नरेश बाल्यान को 30 नवंबर 2024 की रात गिरफ्तार किया था।

दिल्ली में चाकू से वार कर युवक की हत्या

नई दिल्ली। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके की शकूरपुर जेजे कॉलोनी में मामूली कहासुनी के दौरान एक युवक की गर्दन पर चाकू से वार कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपि मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार वारदात गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात करीब एक बजे जी-ब्लॉक रोड पर हुई। योगेश अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां खड़ा था। इसी दौरान एक कार में सवार कुछ युवक वहां पहुंचे। किसी बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। आरोप है कि कार सवार युवकों में से एक ने योगेश की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल योगेश को महाराजा अग्रसेन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से मिली सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शुरुआती जांच में सामने आया है कि हमलावर और मृतक एक-दूसरे के परिचित थे। पुलिस ने आरोपितों की पहचान कर ली है और फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत हैं। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर, 2023 के संसद सुरक्षा चूक मामले के मुख्य आरोपितों में से एक मनोरंजन डी की जमानत याचिका पर शुक्रवार को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश पारित करते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 22 दिसंबर की तारीख तय की है। सुनवाई के दौरान मनोरंजन डी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केके मनन पेश हुए, जबकि दिल्ली पुलिस का पक्ष रखते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक रितेश बाहरी ने नोटिस स्वीकार किया। रितेश ने कोर्ट को सूचित किया कि ट्रायल कोर्ट इस मामले में आरोप तय करने पर एक दिसंबर को अपना आदेश सुनाने वाली है। इससे पहले 13 नवंबर को पटियाला हाउस स्थित एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने मनोरंजन डी और सह-आरोपी सागर शर्मा की दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। स्पेशल जज किरण बंसल ने कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया सही प्रतीत होते हैं, जिससे जमानत पर वैधानिक रोक लागू होती है। गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2023 को 2001 के संसद हमले की बरसी पर मनोरंजन डी और सागर शर्मा दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद गए थे और जूतों में छिपाकर लाए गए केन से सदन में पीला धुआं फैलाया था। इस मामले में पुलिस ने मनोरंजन को 14 दिसंबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।

चालानों की राशि से सडक़ें बनवाए पुलिस : पंकज डावर

गुरुग्राम। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष (शहरी) पंकज डावर ने गुरुग्राम पुलिस द्वारा पिछले 45 दिनों में ट्रैफिक नियम तोडऩे वाले वाहन चालकों के 6 लाख 83 हजार 495 चालान काटकर 140 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने पर कहा कि चालान की इस विशाल राशि को पुलिस जनहित में ही खर्च करे। शहर में अनेक स्थानों पर सडक़ें टूटी पड़ी हैं, उन सडक़ों का निर्माण पुलिस कराए। यह गुडग़ांव की जनता पर पुलिस का उपकार और पुण्य का काम होगा। पंकज डावर ने कहा कि आज गुडग़ांव की जनता का विश्वास सरकार, जीएमडीए, नगर निगम और जिला प्रशासन से पूरी तरह उठ चुका है। जिस शहर को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, स्मार्ट सिटी जैसे बड़े-बड़े नाम दिए गए, उसकी सडक़ों की हालत देखकर लगता है कि यह शहर नहीं, बल्कि गड्ढों का शहर बन गया है। हर चौक-चौराहे पर, हर सेक्टर की सडक़ पर, हर गांव के रास्ते पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। बरसात में ये गड्ढे तालाब बन जाते हैं और सूखे में धूल और मिट्टी से लोगों का जीना दूभर हो जाता है।

दिल्ली विस अध्यक्ष ने संविधान दिवस फोटो प्रदर्शनी का किया उद्घाटन



नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शुक्रवार को नई दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट में संविधान दिवस फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत का संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह हमारे गणराज्य की जीवंत आत्मा है, जिसका निर्माण हमारे संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता, त्याग और कलात्मक विरासत से हुआ है। इस प्रदर्शनी का आयोजन अधिवक्ता परिषद, दिल्ली प्रांत (पटियाला हाउस कोर्ट इकाई) द्वारा नई दिल्ली बार एसोसिएशन के सहयोग से किया गया। उद्घाटन समारोह में विधिक समुदाय के सदस्य, विद्यार्थी एवं आम नागरिक उपस्थित रहे। औपचारिक उद्घाटन के बाद विजेंद्र गुप्ता ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने प्रदर्शित दुर्लभ ऐतिहासिक चित्रों एवं विभिन्न दृश्य सामग्रियों का बारीकी से निरीक्षण किया तथा आयोजकों से इस प्रदर्शनी में समाहित ऐतिहासिक तथ्यों और उनके महत्व पर चर्चा की।

गुप्ता ने अधिवक्ता परिषद और नई दिल्ली बार एसोसिएशन के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल के माध्यम से भारत के लोकतंत्र की आधारशिला से जुड़े इतिहास को विधिक क्षेत्र के पेशेवरों, युवा कानून विद्यार्थियों और आम नागरिकों तक सीधे पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि संविधान सभा की बहसों, आदर्शों और संविधान की मूल पांडुलिपि के पीछे निहित कलात्मक उत्कृष्टता का पुनरावलोकन नागरिक दायित्व की भावना को गहरा करता है तथा दैनिक सार्वजनिक जीवन में संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ बनाता है। गुप्ता ने संविधान सभा की चर्चाओं की कालजयी प्रासंगिकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की रक्षा में विधिक समुदाय के निरंतर योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दुर्लभ अभिलेखीय तस्वीरों, संविधान की मूल पांडुलिपि में की गई कलात्मक चित्रकारी और उन गुमनाम अग्रदूतों की प्रेरक कहानियों को एक साथ प्रस्तुत करना भारत के संवैधानिक इतिहास और भावी पीढ़ियों के बीच एक अमूल्य सेतु का कार्य करता है। गुप्ता ने कहा कि जब युवा अधिवक्ता और विद्यार्थी इन ऐतिहासिक पैनलों के सामने खड़े होते हैं, तो वे केवल अतीत को नहीं देख रहे होते, बल्कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे उन मूल्यों से भी जुड़ रहे होते हैं, जिन्हें हमारे राष्ट्र की भावी यात्रा का मार्गदर्शन करना चाहिए। 'भारत के संविधान का निर्माण, उसकी मूल पांडुलिपि की कला और इसे आकार देने वाले व्यक्तित्व' विषय पर केंद्रित इस प्रदर्शनी में लगभग 50 दृश्य एवं जीवनीपरक पैनल प्रदर्शित किए गए हैं। ये पैनल 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक से लेकर 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किए जाने तक की लगभग तीन वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाते हैं।

आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंची एसीबी

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में आम आदमी पार्टी (आआपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को मिली जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को उन्हें नोटिस जारी किया है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए जैन से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 दिसंबर को होगी।

एसीबी ने राउज एवेन्यू स्थित स्पेशल कोर्ट के 3 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें जैन को जमानत दी गई थी। निचली अदालत ने जमानत देते समय जांच एजेंसी की आलोचना करते हुए कहा था कि प्राथमिकी दर्ज होने के 27 महीने बाद जैन को अचानक और जल्दबाजी में गिरफ्तार किया गया। उच्च न्यायालय में दायर अपनी याचिका में एसीबी ने दलील दी है कि ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि एक ही आपराधिक साजिश में अलग-अलग आरोपियों की भूमिकाएं भिन्न थीं। एजेंसी का आरोप है कि जैन ने मंत्री रहते हुए नीतिगत और प्रशासनिक स्तर पर महत्वपूर्ण फैसले और मंजूरियां दी थीं। एसीबी ने इसे जनता के धन और बुनियादी ढांचे से जुड़ा एक गंभीर आर्थिक अपराध बताते हुए जमानत निरस्त करने का आग्रह किया है। गौरतलब है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के आधुनिकीकरण से जुड़े टेंडर में कथित अनियमितताओं के आरोप में एसीबी ने 18 अगस्त को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था।

इंस्टाग्राम पर सस्ते बैग का लालच देकर 1.04 लाख ठगे, मास्टरमाइंड समेत दो गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने इंस्टाग्राम पर सस्ते सामान का विज्ञापन देकर लोगों को ठगने वाले अंतरराज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया और मास्टरमाइंड समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दक्षिण जिला पुलिस के अनुसार मालवीय नगर निवासी महिला ने इंस्टाग्राम पर 'ञ्चह्य.ड्डह्वष्मद्गह्लद्यद्बह्यह्ल.ह्यह्लश्चहद्द' नाम से एक शॉपिंग पेज देखा था। इस पर बैग की कीमत 999 रुपये बताई गई थी। महिला ने ऑर्डर देने के बाद भुगतान कर दिया। इसके बाद एक व्यक्ति ने खुद को अमेजन का डिलीवरी एजेंट बताकर उनसे संपर्क किया। उसने ऑफर वेरिफिकेशन, प्रोसेसिंग चार्ज और रिफंड एक्टिवेट करने के नाम पर महिला से अलग-अलग किस्तों में 14 बार यूपीआई ट्रांजैक्शन करा लिए। इस तरह महिला से कुल 1,03,973 रुपये ठग लिए गए। शिकायत पर 12 जुलाई को साइबर साउथ थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच के दौरान साइबर पुलिस ने आरोपी के वॉट्सऐप नंबर और तकनीकी जानकारियों का विश्लेषण किया। इससे गिरोह के सदस्यों की पहचान हुई और नेटवर्क का पता जयपुर तक पहुंचा। पुलिस टीम ने स्थानीय पुलिस की मदद से जयपुर के जमवारामगढ़ से अजय मीणा (20) को गिरफ्तार किया। उसके पास से तीन मोबाइल फोन मिले।

इसके बाद तकनीकी निगरानी के जरिए गिरोह के मास्टरमाइंड अशोक कुमार मीणा (32) का पता लगाया गया। उसे 23 नवंबर को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। जांच के दौरान ठगी की रकम में से 1.04 लाख रुपये बरामद कर पीड़िता को वापस करा दिए गए। पुलिस जांच में ठगी का अनोखा तरीका सामने आया। आरोपी इंस्टाग्राम पर फर्जी शॉपिंग पेज बनाकर महंगे सामान को बेहद कम कीमत पर बेचने का विज्ञापन देते थे। ग्राहक के संपर्क करने पर उसे वॉट्सऐप पर बुलाकर अग्रिम भुगतान कराया जाता था। इसके बाद गिरोह का दूसरा सदस्य अमेजन डिलीवरी एजेंट बनकर फोन करता तथा अलग-अलग शुल्क के नाम पर और रकम मांगता था। ठगी की रकम सीधे अपने बैंक खातों में लेने के बजाय आरोपी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के क्यूआर कोड और गेमिंग आईडी के जरिए ट्रांसफर करते थे। इससे पैसों के लेनदेन का पता लगाना मुश्किल हो जाता था। पुलिस को आरोपियों के पास से सात फर्जी इंस्टाग्राम शॉपिंग पेजों का डेटा, फर्जी अमेजन आईडी कार्ड और फर्जी आधार व पैन कार्ड भी मिले हैं।

मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे



गौतमबुद्धनगर। मुख्य विकास अधिकारी भालचंद्र त्रिपाठी की अध्यक्षता में जिला पोषण समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में संभव अभियान, पोषण ट्रैकर, टेक होम राशन, हॉट कुक्ड मील, आंगनबाड़ी केंद्रों की आधारभूत सुविधाओं, सक्षम योजना, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (श्वष्टष्टश्व), दिव्यांगजन सत्यापन, अपार आईडी तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, शिशुओं तथा कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति की समीक्षा करते हुए पोषण एवं कुपोषण प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सैम एवं मैम श्रेणी के बच्चों की नियमित निगरानी, समय से स्वास्थ्य परीक्षण तथा आवश्यकता के अनुसार उन्हें पोषण पुनर्वास केंद्र में संदर्भित करने के निर्देश दिए। साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्र की व्यवस्थाओं एवं कार्यप्रणाली में सुधार लाने पर भी जोर दिया। टेक होम राशन एवं हॉट कुक्ड मील योजना की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि शासन द्वारा निर्धारित मानकों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी पात्र लाभार्थियों को गुणवत्तापूर्ण पोषाहार उपलब्ध कराया जाए। विभिन्न आयु वर्ग के बच्चों, कुपोषित बच्चों तथा गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निर्धारित मानकों के अनुसार पोषाहार वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने आधार फेस मैचिंग एवं एफआरएस से संबंधित कार्यों को भी समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (श्वष्टष्टश्व) की समीक्षा के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत बच्चों की उपस्थिति एवं पोषण ट्रैकर पर आवश्यक सूचनाओं की फीडिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने इस कार्य में लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमित निगरानी करने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर अभिभावक बैठकों का प्रभावी आयोजन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। दिव्यांगजन सत्यापन एवं अपार आईडी की समीक्षा करते हुए उन्होंने शेष बच्चों का सत्यापन शीघ्र पूर्ण कराने तथा पात्र बच्चों की अपार आईडी जनरेट करने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए।

दिल्ली के चार स्पा सेंटरों पर छापेमारी



नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली में मसाज और स्पा सेंटर की आड़ में कथित तौर पर देह व्यापार कराने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने गुरुवार को पहाड़गंज, करोल बाग और नबी करीम इलाके के चार स्पा सेंटरों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान 29 महिलाओं को बचाया गया जबकि स्पा संचालकों, मैनेजरों, रिसेप्शनिस्ट और ग्राहकों समेत 15 लोगों को गिरफ्तार तथा हिरासत में लिया गया।

पुलिस के मुताबिक चारों स्पा सेंटरों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार (निवारण) (आईटीपी) अधिनियम की धाराओं में चार प्राथमिकी दर्ज की गई। स्पा सेंटरों में अवैध गतिविधियां चलने की सूचना मिली थी। इसके बाद संबंधित थानों की टीमों ने डिकॉय कस्टमर (नकली ग्राहक) तैयार किए। पुलिसकर्मी ग्राहक बनकर स्पा सेंटरों में पहुंचे और अतिरिक्त सेवाओं के नाम पर कथित देह व्यापार की गतिविधियों की पुष्टि की। इसके बाद टीमों ने एक साथ छापेमारी की।

पहली कार्रवाई नबी करीम इलाके के राम नगर स्थित 'ए-वन स्पा एंड सैलून' में हुई। यहां डिकॉय कस्टमर बनकर पहुंचे पुलिसकर्मी ने कथित गतिविधियों की पुष्टि की। छापेमारी के दौरान छह महिलाओं को रेस्क्यू कराया गया और स्पा के मालिक, सह-मालिक, मैनेजर समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में आईटीपी अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके अलावा परिसर के मालिक के खिलाफ बीएनएस की धारा 223ए के तहत भी केस दर्ज किया गया है। दूसरी कार्रवाई पहाड़गंज के मुख्य बाजार स्थित 'आर्गेनिक स्पा' में हुई। यहां मैनेजर संप्रिता झा (38) मसाज सेवाओं की आड़ में ग्राहकों को अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध करा रही थी। छापेमारी में तीन महिलाओं को बचाया गया। मौके से पांच हजार रुपये, एक रजिस्टर और पेन बरामद किया गया। मैनेजर को हिरासत में लेकर पाबंद किया गया है। स्पा का लाइसेंस रविता रमन झा के नाम पर जारी हुआ था। करोल बाग के डब्ल्यूईए इलाके में पुलिस ने दो स्पा सेंटरों पर कार्रवाई की। पहली रेड पंजाब स्वीट्स के पास स्थित 'मौर्या स्पा' में की गई। यहां डिकॉय कस्टमर बने पुलिसकर्मी ने 1500 रुपये एडवांस देकर अतिरिक्त सेवा की मांग की। इसके बाद पुलिस ने छापा मारा। यहां से 10 महिलाओं को उनके चंगुल से मुक्त कराया गया। दो मैनेजर सुभंकर और निधि सोनी समेत चार ग्राहकों प्रदीप शर्मा, आयुष माहेश्वरी, मानव सोनी और गगन कैलाशनंद प्रजापति को पकड़ा गया। वहीं, टैंक रोड स्थित 'हेरीटेज स्पा' में डिकॉय कस्टमर ने एक हजार रुपये नकद और एक हजार रुपये ऑनलाइन देकर कथित गतिविधियों की पुष्टि की। छापेमारी में 10 महिलाओं को बचाया गया। पुलिस ने वहां के रिसेप्शनिस्ट-कम-मैनेजर सूरज (20) को पकड़ा। दोनों मामलों में करोल बाग थाने में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने पटेल नगर के ईस्ट पटेल नगर स्थित 'द पैलेस स्पा' और 'द गैलेक्सी स्पा' में भी जांच की। यहां काम करने वाले कर्मचारियों का अनिवार्य पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया था। इस लापरवाही पर दोनों स्पा के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 (ए) के तहत दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने छापेमारी के दौरान नकदी, ग्राहकों के रजिस्टर, कंडोम, लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जब्त किए हैं। पुलिस अब उनके जाल से मुक्त कराई गई महिलाओं के बयान दर्ज करने के साथ पकड़े गए लोगों की भूमिका और इस गतिविधि से जुड़े अन्य लोगों की जांच कर रही है।

नीट पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले के आरोपित डॉ. मनोज भगवानराव शिरुरे की दूसरी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। स्पेशल जज अजय गुप्ता ने जमानत याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई का आदेश दिया। इसके पहले राऊज एवेन्यू कोर्ट 24 जुलाई को शिरुरे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जुलाई में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने शिरुरे की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि ये अपराध राष्ट्र के खिलाफ है। सीबीआई ने कहा था कि इस अपराध ने देश की छवि को खराब किया है और लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। पेपर लीक की वजह से परीक्षा को निरस्त करना पड़ा। कई छात्रों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा।सरकार को भी करीब 600 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। पेपर लीक की घटना के बाद कई छात्रों ने खुदकुशी तक कर ली।

साइबर ठगों को बैंक खाते मुहैया कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट ने साइबर ठगों को फर्जी बैंक खाते मुहैया कराने वाले एक संगठित नेटवर्क का पर्दाफाश कर पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपित साइबर ठगों को ठगी की रकम मंगाने और आगे ट्रांसफर करने के लिए म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। इस नेटवर्क का संबंध कंबोडिया से संचालित हो रहे एक अंतरराष्ट्रीय साइबर क्राइम सिंडिकेट से मिला है। पुलिस के मुताबिक स्पेशल सेल थाने में दर्ज प्राथमिकी जांच के दौरान बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले गिरोह की जानकारी मिली थी।

पता चला कि गिरोह के सदस्य द्वारका इलाके के एक होटल में ठहरे हुए हैं और मेसर्स एमआर ट्रेडर्स के नाम से एचडीएफसी बैंक में खुले खाते का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम को इधर-उधर करने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने छापा मारकर पांच आरोपियों को पकड़ लिया। इस संबंध में स्पेशल सेल थाने में एक और प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच में आरोपियों के मोबाइल फोन से 'एसएमएस टूल्स' नाम का संदिग्ध ऐप मिला। इस ऐप को इस तरह व्यवस्थित किया गया था कि बैंक से आने वाले एसएमएस और ओटीपी अपने आप विदेश में बैठे साइबर अपराधियों तक पहुंच जाएं। इससे ठग दूर बैठकर बैंक खातों का इस्तेमाल कर सकते थे। आरोपियों के फोन से वॉट्सऐप और टेलीग्राम चैट, क्रिप्टोकरेंसी लेन-देन की जानकारी और अन्य डिजिटल सबूत भी मिले हैं। पुलिस को जांच में टेलीग्राम के सात ऐसे चैनलों की जानकारी मिली है, जिनके जरिए म्यूल बैंक खातों की खरीद-फरोख्त की जा रही थी। आरोपित कंबोडिया में सक्रिय साइबर ठगों के लिए स्थानीय स्तर पर बैंक खाते जुटाने और उपलब्ध कराने का काम करते थे। इन खातों के जरिए ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में भेजकर उसका स्रोत छिपाया जाता था। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान-अनीश खान (31), इंतखाब (27), अल्ताफ हुसैन (45), मोहम्मद महफूजार रहमान (41) और इजहार आलम (34) के रूप में हुई है।

आरटीआई केवल उपलब्ध सार्वजनिक रिकॉर्ड तक ही सीमित है : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी पाने का अधिकार केवल उन्हीं रिकॉर्ड्स और सूचनाओं तक सीमित है, जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद हैं या उसके नियंत्रण में हैं। जस्टिस अमित महाजन की पीठ ने आज कहा कि यदि कोई आवेदक विभाग द्वारा आरटीआई के तहत दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है तो केवल इस असंतुष्टि के आधार पर अदालती कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी सुनील भसीन नामक याचिकाकर्ता की याचिका का निपटारा करते हुए की। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव को 28 अक्टूबर, 2020 को भेजे गए अपने एक रिप्रेजेंटेशन की स्थिति, उससे जुड़ी फाइल नोटिंग्स और पत्राचार का विवरण मांगा था। इसके अलावा, उन्होंने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन द्वारा सेवा से बर्खास्तगी के खिलाफ दायर अपनी 6 जून, 2019 की अपील से जुड़े दस्तावेज भी



आरटीआई के जरिए मांगे थे। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पाया कि संबंधित प्राधिकरणों ने अपने पास उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर याचिकाकर्ता को जवाब दे दिया था। जस्टिस महाजन ने कहा कि आरटीआई कानून का उद्देश्य मौजूदा सार्वजनिक रिकॉर्ड तक पारदर्शी पहुंच प्रदान करना है, न कि किसी विभाग को ऐसी जानकारी तैयार करने या जुटाने के लिए बाध्य करना जो उसके पास उपलब्ध ही नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध रिकॉर्ड साझा कर दिया गया है तो आवेदक की व्यक्तिगत असंतुष्टि के आधार पर रिट याचिका को लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

नाबालिगों से दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 साल की कैद

फरीदाबाद,एजेंसी। नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के तीन अलग-अलग मामलों में अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार भांकर की अदालत ने तीनों दोषियों को 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। तीनों मामलों में पीड़ित पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेश चौधरी ने पैरवी की। पहला मामला सेक्टर-58 थाना क्षेत्र का है। 21 जनवरी 2024 को एक महिला ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने की शिकायत पुलिस को दी थी। महिला के अनुसार, उसकी बेटी को अनियमित मासिक धर्म की परेशानी थी। डॉक्टर से उपचार कराने के बावजूद जब समस्या दूर नहीं हुई तो डॉक्टर की सलाह पर मां ने बेटी से बातचीत की। इस दौरान किशोरी ने बताया कि उसका ताऊ का बेटा काफी समय से उसके साथ गलत काम कर रहा था। डर के कारण उसने पहले किसी को इसकी जानकारी नहीं दी थी। इसके बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

दूसरा मामला 20 मार्च 2021 को संजय कॉलोनी चौकी में दर्ज हुआ था। 14 वर्षीय किशोरी



की मां ने पड़ोस में रहने वाले राजन पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच के दौरान किशोरी को बिहार से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। किशोरी ने पुलिस को दिए बयान में आरोपी पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अदालत में चालान पेश किया। तीसरा मामला पल्ला थाना क्षेत्र का है। इसमें 16 वर्षीय किशोरी की मां ने रोहित नामक युवक पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। पुलिस ने जांच के दौरान किशोरी को दिल्ली के मदनपुर खादर से बरामद किया था। किशोरी ने आरोपी पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस की जांच और कानूनी कार्रवाई के बाद यह मामला भी अदालत पहुंचा। तीनों मामलों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। एडिशनल सेशन जज राकेश कुमार भांकर की अदालत ने प्रत्येक दोषी को 20 साल के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अधिवक्ता संतोष भारद्वाज ने बताया कि तीनों मामलों में पीड़ित पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेश चौधरी ने अदालत में प्रभावी पैरवी की थी।

खेतों से दुनिया तक भारतः अन्न उत्पादन का कीर्तिमान कृषि शक्ति का प्रमाण

डॉ. मयंक चतुर्वेदी



भारत के खेतों में इस बार जो इतिहास रचा गया है। यह उस किसान के परिश्रम, संकल्प और सामर्थ्य का प्रमाण है, जो मौसम की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक चुनौतियों और खेती की बढ़ती लागत के बीच भी देश के अन्न भंडार भरने में जुटा रहता है। वर्ष 2025-26 में देश का खाद्यान्न उत्पादन 3785.38 लाख टन तक पहुंचना और पिछले वर्ष की तुलना में 208.06 लाख टन की वृद्धि दर्ज करना भारतीय कृषि की असाधारण उपलब्धि है। दूसरी ओर भारतीय कृषि की बढ़ती ताकत का एक महत्वपूर्ण प्रमाण कृषि निर्यात भी है। प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों सहित भारत का कृषि-खाद्य निर्यात लगातार कई अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का सरकारी आंकड़ा सामने आया है। यह बताता है कि भारत की कृषि अब घरेलू खाद्य जरूरतों को पूरा करने के साथ वैश्विक व्यापार में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

वस्तुतः चावल, दलहन, जूट, मोटे अनाज और मसालों के उत्पादन में दुनिया में प्रथम स्थान हासिल करना इस उपलब्धि को वैश्विक महत्व प्रदान करता है। सवाल यह है कि क्या इस कीर्तिमान को भारत की कृषि व्यवस्था में निर्णायक बदलाव का संकेत माना जाए? इसका उत्तर निश्चित रूप से सकारात्मक है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2025-26 के अंतिम उत्पादन अनुमान और 2026-27 के खरीफ सीजन के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी करते हुए जिस उपलब्धि को सामने रखा है, उसके कई महत्वपूर्ण आयाम हैं। भारत में चावल का उत्पादन 1551.54 लाख टन और गेहूं का उत्पादन 1220.64 लाख टन तक पहुंचना बताता है कि देश की खाद्य सुरक्षा का आधार लगातार मजबूत हुआ है। मक्का उत्पादन में 550.25 लाख टन तक की छलांग और दलहन उत्पादन का 272.40 लाख टन पर पहुंचना भी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। आज भारत चावल, दलहन, जूट, श्री अन्न और मसालों के उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। गेहूं, कपास और मूंगफली सहित कई अन्य उत्पादों में भी भारत की स्थिति मजबूत है। भारतीय चावल के निर्यात में पांच प्रतिशत की वृद्धि और अमेरिका, कनाडा तथा मध्य पूर्व के बाजारों में बासमती की बढ़ती मांग इस बात का संकेत है कि भारतीय कृषि उत्पादों की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है। इस वर्ष खरीफ उत्पादन का अनुमान भारतीय किसानों की जिजीविषा का एक और प्रमाण है। अल नीनो की आशंका, मानसून में देरी और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में कम बारिश के बावजूद खरीफ खाद्यान्न उत्पादन 1671.43 लाख टन रहने का अनुमान है। यह पिछले पांच वर्षों के औसत से 97.67 लाख टन अधिक है। यह भारत के लिए निश्चित ही विशेष उपलब्धि है।

खाद्यान्न के बाद अब दलहन और तिलहन की बारी

भारतीय कृषि की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक दालों और खाद्य तेलों के मामले में आयात पर निर्भरता रही है। गेहूं और चावल के पर्याप्त भंडार होने के बाद अब सरकार का दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना समय की मांग है। वर्ष 2025-26 में दलहन उत्पादन 272.40 लाख टन और तिलहन उत्पादन 432.55 लाख टन तक पहुंचना उत्साहजनक है। मूंगफली का 131.71 लाख टन और सरसों का 137.66 लाख टन उत्पादन नए अवसरों की ओर संकेत करता है, किंतु साथ ही हमें यह सोचने के लिए विवश करता है कि आखिर जब देश में दालों और खाद्य तेलों की मांग लगातार बढ़ रही है, तब आयात पर निर्भरता कब तक स्वीकार की जा सकती है? वस्तुतः इसका समाधान किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने में है, जिनकी घरेलू मांग अधिक है और जिनसे उन्हें बेहतर आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसके लिए किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उन्नत तकनीक, सिंचाई, कृषि यंत्र और बाजार की सुनिश्चित उपलब्धता देनी होगी। दलहन और तिलहन की खेती में जोखिम कम करने के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन तथा खरीद व्यवस्था भी जरूरी है। किसान तभी फसल विविधीकरण की ओर बढ़ेगा, जब उसे यह भरोसा होगा कि उसकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और बाजार में उसे भटकना नहीं पड़ेगा। आज भारत के सामने एक ऐसा अवसर है, जिसका उपयोग दूरगामी कृषि परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। देश ने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मविश्वास हासिल किया है। वैश्विक कृषि रैंकिंग में उसकी स्थिति मजबूत हुई है और निर्यात की संभावनाएं बढ़ी हैं। अब आवश्यकता इस उपलब्धि को टिकाऊ कृषि व्यवस्था में बदलने की है। निश्चित ही 3785.38 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन का कीर्तिमान भारत के लिए गौरव का विषय है। यह उस किसान की मेहनत का सम्मान है, जो देश की खाद्य सुरक्षा का सबसे मजबूत प्रहरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारतीय कृषि और किसानों की सामर्थ्य को देश की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण आधार माना है। उनका स्पष्ट दृष्टिकोण रहा है कि किसान सशक्त होगा तो देश समृद्ध होगा और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा तो भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बीज से बाजार तक' के दृष्टिकोण को इसी व्यापक अर्थ में समझना होगा। भारत की कृषि शक्ति का वास्तविक उत्कर्ष तब होगा, जब खेत में लहलहाती फसल के साथ किसान के घर में भी समृद्धि आएगी। आखिरकार किसी देश की कृषि महानता का आकलन उसके अन्न भंडारों की ऊंचाई से ही होता है। ऐसे में उसके जीवन में खुशहाली का होना भी जरूरी है। आज भारत ने अन्न उत्पादन में इतिहास रचा है, अब उसे किसान की समृद्धि का नया इतिहास रचना है। यही विकसित भारत के संकल्प की दिशा में कृषि क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा।

महिलाओं की सत्ता में दमदार भागीदारी के बावजूद संभावना जताते हुए सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह पंचायतों में सरपंच पति, प्रधान पति या पंच पति का दौर चला था, क्या उसी तरह प्रमुख पति के रुप में राजनीतिक सक्रियता दिखेगी। सच्चे मायने में महिला जिला प्रमुख ही सत्ता की भागीदार बने और निर्णय जिला प्रमुख का ही रहे, जिला प्रमुख पति आदि का नहीं। कहने का अर्थ यह है कि महिलाओं को निर्णय क्षमता विकसित करनी होगी और प्रशासन में अपनी निर्णय क्षमता और कार्यशैली की छाप छोड़ने की चुनौती महिला जिला प्रमुखों के सामने होगी। राज्य सरकार को भी नई जिला प्रमुखों आदि के लिए ओरियंटेशन कार्यक्रम व्यापक व निरंतरता के साथ आयोजित करने होंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी सच्चे मायने में उभरकर आ सके। सत्ता में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वैश्विक औसत 27.5 फीसदी है। 30 देशों में राष्ट्राध्यक्ष महिला है तो दुनिया के केवल 8 देश ही ऐसे हैं जहां महिलाओं की भागीदारी 50 फीसदी से अधिक है। रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, कोस्टारिका, बोलिविया, मैक्सिको, एंडोरा और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड 45 से 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। इस समय दुनिया के 56 देश ऐसे हैं जहां सत्ता में महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।

राजस्थानः सत्ता में महिलाओं की भागीदारी के नए संकेत

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा



राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव परिणामों को लेकर किसका पलड़ा भारी या कमजोर रहा या चुनाव परिणामों का राजस्थान की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, यह राजनीति विज्ञों के बीच अलग विचार का मुद्दा हो सकता है पर राजस्थान से जिला प्रमुखों के चुनाव परिणाम से जिस तरह सत्ता में भागीदारी में सशक्तिकरण उभर का आया है वह एक सकारात्मक संकेत है। राजस्थान के नागौर से पंचायतीराज का बिगुल बजा था और आज जिला प्रमुखों के 70 फीसदी महिलाओं की हिस्सेदारी की नई बयार देखने को मिल रही है। सत्ता में महिलाओं की भागीदारी को लेकर राजस्थान से सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। राजस्थान में जिला प्रमुखों के चुनाव परिणाम न केवल चौंकाने वाले हैं अपितु आने वाले समय में महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ने की दिशा में बढ़ता कदम माना जा सकता है। राजस्थान में 37 जिला परिषदों के परिणामों में 26 जिला परिषदों में जिला प्रमुख के पद पर महिलाएं चुनी गई है। इसमें भी खास बात यह है कि सुदूर रेगिस्तानी जिले जैसलमेर से महज 21 साल और एक माह की आयु की संतोष कुमारी जिला प्रमुख चुनी गई है तो 21 वर्ष और 4 माह की वर्षा झाला झालावाड़ की जिला प्रमुख चुनी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि जिला प्रमुख बनने वाली महिलाओं में अधिकांश जहां युवा हैं तो दूसरी ओर अच्छी पढ़ी-लिखी महिलाएं जिला प्रमुख बनी है। देखा जाए तो महिलाओं में भी राजस्थान में शिक्षित और युवा महिला नेतृत्व उभर कर आया है। इसे भविष्य के लिए शुभ संकेत माना जा सकता है। महिलाओं की सत्ता में भागीदारी से यह भी माना जा सकता है कि महिलाएं जमीनी हकीकत से अधिक जुड़ी होती है, ऐसे में पंचायतीराज संस्थाओं में स्थानीय स्तर की समस्याओं के समाधान में सार्थक और सकारात्मक परिणाम की आशा की जा सकती है। माना जा रहा है कि युवा और शिक्षित महिला नेतृत्व का फोकस शुद्ध पेयजल से लेकर बिजली, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी और स्थानीय स्तर की समस्याओं को समझने और उनके निराकरण में अधिक सकारात्मकता आएगी। माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर भी एक हद तक रोक संभव हो पाएगी तो महिलाएं नए जोश और नई ऊर्जा से काम करते हुए परिणाम देने का प्रयास करेंगी। कुल मिलाकर कार्य व्यवस्था में बदलाव की संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता।

महिलाओं की सत्ता में दमदार भागीदारी के बावजूद संभावना जताते हुए सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह पंचायतों में सरपंच पति, प्रधान पति या पंच पति का दौर चला था, क्या उसी तरह प्रमुख पति के रुप में राजनीतिक सक्रियता दिखेगी। सच्चे मायने में महिला जिला प्रमुख ही सत्ता की भागीदार बने और निर्णय जिला प्रमुख का ही रहे, जिला प्रमुख पति आदि का नहीं। कहने का अर्थ यह है कि महिलाओं को निर्णय क्षमता विकसित करनी होगी और प्रशासन में अपनी निर्णय क्षमता और कार्यशैली की छाप छोड़ने की चुनौती महिला जिला प्रमुखों के सामने होगी। राज्य सरकार को भी नई जिला प्रमुखों आदि के लिए ओरियंटेशन कार्यक्रम व्यापक व निरंतरता के साथ आयोजित करने होंगे ताकि महिलाओं की भागीदारी सच्चे मायने में उभरकर आ सके। सत्ता में महिलाओं की भागीदारी की बात करें तो वैश्विक औसत 27.5 फीसदी है। 30 देशों में राष्ट्राध्यक्ष महिला है तो दुनिया के केवल 8 देश ही ऐसे हैं जहां महिलाओं की भागीदारी 50 फीसदी से अधिक है। रवांडा, क्यूबा, निकारागुआ, कोस्टारिका, बोलिविया, मैक्सिको, एंडोरा और संयुक्त अरब अमीरात में 50 प्रतिशत से अधिक भागीदारी है। न्यूजीलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड 45 से 50 प्रतिशत महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। इस समय दुनिया के 56 देश ऐसे हैं जहां सत्ता में महिलाओं का 33 प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।

पिछले चुनाव में सरकार बनाने में महिलाएं निर्णायक भूमिका में रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 14 राज्यों में महिलाओं की निर्णायक भूमिका रही। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी 19 राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में महिलाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों के चुनाव परिणामों का विश्लेषण करें तो यह भी साफ हो जाता है कि लगभग सभी पार्टियों ने महिलाओं को केन्द्र में रखकर चुनाव घोषणापत्र बनाये और महिलाओं को किसी भी नाम से योजना रखते हुए एक निश्चित राशि देने की बात प्रमुखता से की। राजनीतिक पार्टियां कहने को कुछ भी कहे या महिलाओं को आगे लाने की कितनी भी बात करें पर विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी अभी तक बढ़ नहीं पाई है। महिला प्रतिनिधित्व का वैश्विक औसत जहां 27.5 प्रतिशत है, वहीं हमारे देश में अभी तक यह 14-15 प्रतिशत तक पहुंच पाया है। रोचक बात यह है कि साल 2009 की 15वीं लोकसभा के पहले तक हमारे देश में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व दहाई की संख्या में भी नहीं पहुंचा था। 15वीं लोकसभा में पहली बार 10.9 प्रतिशत प्रतिनिधित्व हो सका। हालांकि साल 1977 में आपातकाल के ठीक बाद की लोकसभा में सबसे कम भागीदारी केवल 3.5 प्रतिशत ही रह गई थी। पर 1977 के हालात अलग थे और उनको अलग करके देखा जाना चाहिए। उस समय आपात्काल के बाद की स्थितियां थी। 18वी लोकसभा में 17 वीं लोकसभा की तुलना में 3 महिला सांसद कम है। इस तरह से 17वीं लोकसभा में महिलाओं की सर्वाधिक 14.4 प्रतिशत भागीदारी रही। इन सब हालातों में राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं में जिला प्रमुख की जिम्मेदारी 70 फीसदी से अधिक महिलाओं और खासतौर से युवा और शिक्षित महिलाओं के हाथ में आई है तो इससे राजनीतिक परिदृश्य के लिए शुभ और सकारात्मक संदेश माना जाना चाहिए। इसके साथ ही महिला जिला प्रमुखों से भी यह अपेक्षा रहेगी वे स्वयं निर्णय लेने और विकास में भागीदार बनने का संदेश दें।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

विचार

पंजाबः पर्दे के पीछे ऐसे बुनी गई छह साल बाद वापसी की पटकथा

सुदेश गौड़

राजनीति में किसी गठबंधन की घोषणा भले ही मंच पर दो-चार बड़े नेता करते दिखाई दें लेकिन उसके पीछे कई ऐसे चेहरे होते हैं जो महीनों तक संवाद, गणित, सर्वेक्षण, असहमतियों और राजनीतिक संभावनाओं पर काम करते हैं। पंजाब में भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के बीच छह साल बाद हुआ गठबंधन इसका दिलचस्प उदाहरण है। यहां हुए राजनीतिक पुनर्मिलन के पीछे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राजनीतिक इच्छाशक्ति, गुजरात से उनके पुराने सहयोगी सीआर पाटिल की चुनावी रणनीति, पूर्व भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की शुरुआती पहल, पंजाब से मिले जमीनी फीडबैक और कुछ ऐसे नेताओं के प्रयास हैं जिन्होंने दोनों दलों के बीच भरोसे की जमीन तैयार की। इस गठबंधन की असली कहानी पर्दे के पीछे इन्हीं काम करने वाले नायकों की है। इस पूरी कवायद के सबसे महत्वपूर्ण सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रहे। उन्होंने राजग के पुराने सहयोगियों को फिर साथ लाने की राजनीतिक जरूरत को समझा। हाल ही में राजग के सहयोगी दलों की एक बैठक में मोदी ने अकाली दल के दिवंगत नेता प्रकाश सिंह बादल, शिवसेना के बाल ठाकरे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्नेहपूर्वक उल्लेख किया था। इसे पुराने सहयोगियों के प्रति सम्मान और राजनीतिक संबंधों को फिर मजबूत करने के संकेत के रूप में देखा गया। इसके बाद अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री मोदी और सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात हुई। साल 2020 में गठबंधन टूटने के बाद यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण थी। इसने दोनों दलों के बीच जमी बर्फ पिघलाने का काम किया। मोदी ने इस मामले को केवल सीटों और सत्ता के गणित तक सीमित नहीं रखा। पंजाब की आर्थिक स्थिति, सामाजिक सद्भाव, नशे की समस्या और सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा जैसे व्यापक विषय भी इस राजनीतिक पुनर्समीक्षा का हिस्सा बने।

इस घटनाक्रम में सबसे उल्लेखनीय पर्दे के पीछे का नाम सीआर पाटिल का है। गुजरात की राजनीति में नरेन्द्र मोदी के साथ लंबे समय तक काम कर चुके सीआर पाटिल को पंजाब में भाजपा की चुनावी संभावनाओं का आकलन करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने अलग-अलग स्तरों पर जमीनी सर्वेक्षण करवाए। इनका उद्देश्य केवल भाजपा की लोकप्रियता जानना नहीं था बल्कि यह समझना भी था कि अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर राजनीतिक परिणाम किस तरह बदल सकते हैं। सर्वेक्षणों से जो निष्कर्ष सामने आए, वे भाजपा नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण थे। यही वह मोड़ था जहां गठबंधन की राजनीतिक इच्छा को चुनावी आंकड़ों का आधार मिला। अकाली दल और भाजपा के बीच रिश्ते सितंबर 2020 में कृषि कानूनों के विरोध के कारण टूट गए थे। दोनों दलों के बीच करीब 24 वर्ष पुराना गठबंधन समाप्त हो गया था। इसके बाद 27 अप्रैल 2023 को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने लांबी पहुंचे। यह केवल एक शोकसभा में उपस्थिति नहीं थी। साल 2020 में अलगाव के बाद दोनों दलों के नेताओं का एक साथ दिखाई देना संबंधों में नरमी का पहला सार्वजनिक संकेत बना। नड्डा की इस पहल ने यह संदेश दिया कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद पुराने संबंधों और सहयोगियों के प्रति सम्मान कायम है। इस घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि चर्चाओं के अनुसार अमित शाह शुरुआत में अकाली दल के साथ गठबंधन को लेकर बहुत उत्साहित नहीं थे। भाजपा का एक वर्ग चाहता था कि पार्टी पंजाब में अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार विकसित करे। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पंजाब में अपनी स्थिति बेहतर की थी लेकिन सीआर पाटिल के सर्वेक्षण, पंजाब से मिले राजनीतिक फीडबैक और व्यापक राष्ट्रीय परिस्थितियों के आकलन ने तस्वीर बदल दी। शाह की पंजाब यात्राओं के दौरान नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले परिवारों से संवाद महत्वपूर्ण रहा। इन मुलाकातों ने पंजाब की वास्तविक समस्याओं को राजनीतिक नेतृत्व के सामने अधिक स्पष्ट किया। अंततः शाह ने गठबंधन के पक्ष में सहमति बनाई। शाह की भूमिका को केवल गठबंधन की घोषणा करने वाले नेता के रूप में नहीं बल्कि शुरुआती असहमति से अंतिम सहमति तक पहुंचे निर्णायक सूत्रधार के रूप में है। पंजाब की राजनीति और वहां के सामाजिक समीकरणों की रवनीत सिंह बिट्टू की समझ भाजपा के लिए उपयोगी रही है। बिट्टू मानते भी हैं कि भाजपा का अकाली दल के साथ वापस आने का निर्णय पंजाब की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले फीडबैक पर आधारित है। जमीनी स्तर पर दोनों दलों के साथ आने की मांग महसूस की जा रही थी। बिट्टू की भूमिका को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि भाजपा को पंजाब में केवल चुनावी सर्वेक्षणों की नहीं बल्कि स्थानीय राजनीतिक मनोदशा की भी जानकारी चाहिए थी। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की नाराजगी, सिख मतदाताओं का रुख, अकाली दल की संगठनात्मक स्थिति और भाजपा के प्रति स्थानीय प्रतिक्रिया जैसे विषयों पर जमीनी फीडबैक का महत्व था।

दिल्ली-बिहार के बीच 18 मार्गों पर अंतरराज्यीय बस सेवा का विस्तार, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने बस सेवा को दिखाई हरी झंडी



नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली और बिहार के बीच अंतरराज्यीय परिवहन व्यवस्था को अधिक सुगम, व्यवस्थित और मजबूत बनाने की दिशा में शुक्रवार को महत्वपूर्ण पहल की गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की उपस्थिति में दिल्ली और बिहार सरकार के बीच 18 मार्गों पर पारस्परिक परिवहन समझौता संपन्न हुआ। इस एमओयू के माध्यम से दोनों राज्यों के बीच नियमित अंतरराज्यीय बस सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जिससे आम नागरिकों, कामगारों, श्रमिकों और अन्य यात्रियों को वर्षभर सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कश्मीरी गेट स्थित महाराणा प्रताप अंतरराज्यीय बस टर्मिनल (आईएसबीटी) से दिल्ली-बिहार अंतरराज्यीय बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष कार्यक्रम में बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत, दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज सिंह सहित दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज दिल्ली और बिहार के लिए अत्यंत खुशी का अवसर है। दोनों राज्य सरकारों के बीच हुए परिवहन समझौते के तहत दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने बिहार सरकार को 18 अंतरराज्यीय मार्गों पर बस संचालन के लिए 216 परमिट प्रदान किए हैं। इन मार्गों पर दिल्ली से बिहार के विभिन्न शहरों तक बसों का संचालन किया जाएगा। यह उपलब्धि दोनों राज्यों के बीच मजबूत होते संबंधों और आपसी सहयोग का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाखों बिहारवासी दिल्ली आकर अपनी मेहनत से राजधानी को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं। दिल्ली और बिहार के बीच निर्धारित किए गए ये मार्ग उन लाखों विद्यार्थियों के लिए भी सुविधाजनक होंगे, जो यहां पढ़ने या काम करने आते हैं। दिल्ली सरकार चाहती है कि दिल्ली या बिहार में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस सुविधा से दिल्ली में रहने और काम करने वाले बिहार व पूर्वांचल के लगभग 15 से 20 लाख लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से छठ, दीपावली और दशहरा जैसे त्योहारों के दौरान अत्यधिक भीड़ के कारण अपने घर जाने में होने वाली परेशानियों से उन्हें काफी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों की मांग और आवश्यकता के अनुरूप भविष्य में बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। डॉ. सिंह ने कहा कि वह स्वयं पूर्वांचल की माटी से जुड़े हुए हैं और इस क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं तथा यहां के लोगों की भावनाओं को भली-भांति समझते हैं। ऐसे में पूर्वांचल और बिहार के लाखों लोगों की वर्षों पुरानी आवागमन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने की दिशा में इस पहल का हिस्सा बनना उनके लिए व्यक्तिगत रूप से भी अत्यंत हर्ष का विषय है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह समझौता न केवल लोगों की यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि दिल्ली और बिहार के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को भी और अधिक मजबूत करेगा। कार्यक्रम में बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि इस पहल के माध्यम से पटना, गयाजी, दरभंगा, मधुबनी और भागलपुर सहित बिहार के 13 शहरों एवं क्षेत्रों के लिए दिल्ली से सीधी बस सेवाएं उपलब्ध होंगी। इससे दिल्ली में रहने वाले बिहारवासियों को पर्व-त्योहारों के साथ-साथ सामान्य दिनों में भी अपने घर और परिवार तक पहुंचने में अधिक सुविधा मिलेगी। दिल्ली और बिहार के बीच बड़ी संख्या में नागरिकों, कामगारों और श्रमिकों का आवागमन होता है। लगभग 20 लाख कामगार एवं श्रमिक दिल्ली में निवास और कार्य करते हैं। ऐसे में दोनों राज्यों के बीच नियमित अंतरराज्यीय बस सेवा का विस्तार उनकी यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस समझौते के तहत बिहार के विभिन्न शहरों से दिल्ली के बीच 18 मार्गों पर बस संचालन के लिए परिवहन व्यवस्था निर्धारित की गई है। प्रत्येक मार्ग के लिए दिल्ली और बिहार, दोनों की ओर से 12-12 परमिट कोटा निर्धारित किया गया है। इससे दोनों राज्यों के बीच बस सेवाओं के संचालन को नियमित एवं व्यवस्थित रूप देने में सहायता मिलेगी। समझौते के तहत निर्धारित मार्गों में बिहार के विभिन्न प्रमुख शहरों को दिल्ली से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। समझौते के तहत बिहार के विभिन्न प्रमुख शहरों से दिल्ली के लिए अंतरराज्यीय बस सेवा संचालित की जाएगी। इसके तहत अररिया, बिहारशरीफ, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा, पूर्वी चंपारण, गया, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नवादा, पटना और पूर्णिया से दिल्ली के लिए बसें चलेंगी। पटना, गया और मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए एक से अधिक मार्गों पर बस सेवा उपलब्ध होगी। इन मार्गों के माध्यम से बिहार के विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली तक यात्रियों को बेहतर अंतरराज्यीय बस कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। मार्गों में उत्तर प्रदेश और दिल्ली से होकर गुजरने वाले प्रमुख शहरों एवं परिवहन केंद्रों को शामिल किया गया है।



प्रमुख मार्गों पर बस किराया-

बीएसआरटीसी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, प्रमुख मार्गों पर दूरी और बस की श्रेणी के आधार पर किराया निर्धारित किया गया है।

1. **पटना-दिल्ली (1,198 किमी) :** नॉन-एसी सीटर 1,615 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 1,715 रुपये, एसी सीटर 1,980 रुपये और एसी स्लीपर 2,919 रुपये।
2. **मुजफ्फरपुर-दिल्ली (1,071 किमी):** नॉन-एसी सीटर 1,470 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 1,570 रुपये, एसी सीटर 1,804 रुपये और एसी स्लीपर 2,717 रुपये।
3. **गयाजी-दिल्ली (1,106 किमी):** नॉन-एसी सीटर 1,555 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 1,655 रुपये, एसी सीटर 1,907 रुपये और एसी स्लीपर 2,784 रुपये।
4. **दरभंगा-दिल्ली (1,137 किमी):** नॉन-एसी सीटर 1,592 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 1,692 रुपये, एसी सीटर 1,853 रुपये और एसी स्लीपर 2,866 रुपये।
5. **पूर्णिया-दिल्ली (1,367 किमी):** नॉन-एसी सीटर 2,018 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 2,118 रुपये, एसी सीटर 2,470 रुपये और एसी स्लीपर 3,383 रुपये।
6. **भागलपुर-दिल्ली (1,420 किमी) :** नॉन-एसी सीटर 1,917 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 2,017 रुपये, एसी सीटर 2,347 रुपये और एसी स्लीपर 3,256 रुपये।
7. **अररिया-दिल्ली (1,319 किमी) :** नॉन-एसी सीटर 1,929 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 2,029 रुपये, एसी सीटर 2,362 रुपये और एसी स्लीपर 3,275 रुपये।
8. **किशनगंज-दिल्ली (1,427 किमी):** नॉन-एसी सीटर 2,011 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 2,111 रुपये, एसी सीटर 2,463 रुपये और एसी स्लीपर 3,375 रुपये।
9. **मोतिहारी-दिल्ली (1,071 किमी):** नॉन-एसी सीटर 1,429 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 1,529 रुपये, एसी सीटर 1,755 रुपये और एसी स्लीपर 2,694 रुपये।
10. **सीतामढ़ी-दिल्ली (1,130 किमी):** नॉन-एसी सीटर 1,579 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 1,679 रुपये, एसी सीटर 1,937 रुपये और एसी स्लीपर 2,850 रुपये।
11. **शिवहर-दिल्ली (1,118 किमी):** नॉन-एसी सीटर 1,559 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 1,659 रुपये, एसी सीटर 1,913 रुपये और एसी स्लीपर 2,821 रुपये।
12. **सीवान-दिल्ली (962 किमी):** नॉन-एसी सीटर 1,276 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 1,376 रुपये, एसी सीटर 1,568 रुपये और एसी स्लीपर 2,467 रुपये।
13. **सुपौल-दिल्ली (1,285 किमी):** नॉन-एसी सीटर 1,774 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 1,874 रुपये, एसी सीटर 2,175 रुपये और एसी स्लीपर 3,114 रुपये।
14. **लौकहा-दिल्ली (1,322 किमी):** नॉन-एसी सीटर 1,844 रुपये, नॉन-एसी स्लीपर 1,944 रुपये, एसी सीटर 2,257 रुपये और एसी स्लीपर 3,176 रुपये।

अन्य मार्गों के किराये, बसों की समय-सारणी और ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जानकारी बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के पोर्टल www.bsrtc.bihar.gov.in पर उपलब्ध होगी।

एक नजर

बाल विवाह उन्मूलन को लेकर कटिहार में निकली भव्य प्रभात फेरी



कटिहार। बाल, कम आयु एवं जबरन विवाह के उन्मूलन के लिए मनाए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुक्रवार को समाहरणालय परिसर से एक भव्य जागरूकता प्रभात फेरी निकाली गई। जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने हरी झंडी दिखाकर प्रभात फेरी को रवाना किया। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने उपस्थित छात्र-छात्राओं, अधिकारियों और गणमान्य लोगों को बाल विवाह के विरुद्ध सामूहिक शपथ भी दिलाई। प्रभात फेरी में शामिल स्कूली बच्चे, शिक्षक, समाजसेवी और जिला स्तरीय पदाधिकारी हाथों में जागरूकता बैनर, पोस्टर व तख्तियां लिए चल रहे थे। समाहरणालय परिसर से प्रारंभ हुई यह प्रभात फेरी शहीद चौक, मिर्चाईबाड़ी और हनुमान मंदिर चौक होते हुए पुनः समाहरणालय परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान बच्चों ने 'बाल विवाह नहीं, पढ़ाई और सपनों की उड़ान है', 'बाल विवाह रोको-बेटी पढ़ाओ', 'कम उम्र में शादी नहीं, पढ़ाई है जरूरी' तथा 'बाल विवाह अपराध है - आओ इसे रोकें' जैसे गगनभेदी नारों के माध्यम से आम लोगों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, युवाओं, सामाजिक संगठनों व मीडियाकर्मियों से इस जन-जागरूकता अभियान को सफल बनाने तथा कहीं भी बाल विवाह होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1098, 181 या 112 पर सूचना देने की अपील की है।

पॉक्सो मामलों की जांच में न हो विलंब, गोपनीय रखी जाए पीड़ित की पहचान



कटिहार। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार (27 नवंबर 2026) को वृहद आश्रय गृह, कटिहार में जिले के सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच में किसी प्रकार का विलंब न हो, पीड़ित बच्चे की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए और उस पर कोई मानसिक दबाव न डाला जाए। प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों के प्रति संवेदनशीलता ही असली पुलिसिंग है। जब कोई बच्चा थाने आता है, तो वह अपराधी नहीं बल्कि सहायता की उम्मीद लेकर आता है, इसलिए उसके साथ बाल मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम के तहत विधि से संघर्षरत किशोरों के प्रति दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए तथा सभी पदाधिकारी अपने-अपने थानों में बाल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों ने पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध की परिभाषा, प्राथमिकी दर्ज करने, मेडिकल जांच व बयान लेने की प्रक्रिया, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड व जिला बाल संरक्षण इकाई की भूमिका, बाल मैत्रीपूर्ण पुलिस स्टेशन की अवधारणा, बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल श्रम एवं गुमशुदा बच्चों के मामलों में पुलिस के दायित्व तथा हेल्पलाइन नंबर 1098, 181 व 112 की कार्यप्रणाली पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक के प्रतिनिधि, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रतिनिधि, बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य तथा जिले के सभी थानों के बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे।

बाल विवाह के खिलाफ प्रशासन सख्त, डीएम ने कहा- किशनगंज में अब नहीं होगा बाल विवाह

किशनगंज। बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए किशनगंज प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय बाल, प्रारंभिक एवं जबरन विवाह उन्मूलन दिवस के अवसर पर शहर के खेल भवन में एक दिवसीय जिला स्तरीय जागरूकता एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी नवीन कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिले में बाल विवाह किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाल विवाह कराने, उसमें सहयोग देने अथवा उसे बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि बाल विवाह केवल सामाजिक कुरीति नहीं, बल्कि बच्चों के मौलिक अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के साथ गंभीर अन्याय है। बाल विवाह मुक्त किशनगंज बनाना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज का सामूहिक संकल्प होना चाहिए। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि बाल विवाह रोकने के लिए आगे आएं, ताकि हर बेटी को शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और अपने सपनों के अनुसार जीवन जीने का अवसर मिल सके। कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आईसीडीएस सह डब्ल्यूसीडीसी की नोडल पदाधिकारी बंदना पांडेय के मार्गदर्शन में किया गया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए जागरूकता को जनआंदोलन का रूप देना होगा। इसके लिए आंगनबाड़ी सेविकाओं, महिला पर्यवेक्षिकाओं, एएनएम, स्वास्थ्य कर्मियों, पंचायत प्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने प्रतिभागियों से अपने-अपने क्षेत्रों में जागरूकता फैलाने और बाल विवाह की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने बाल विवाह के सामाजिक, कानूनी, प्रशासनिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों पर विस्तार से जानकारी दी। जन निर्गम केंद्र के जिला समन्वयक मो. मुजाहिद आलम ने बाल विवाह निषेध कानून, दोषियों की कानूनी जवाबदेही और पीड़ित बच्चों के अधिकारों के बारे में बताया।

अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की तैयारियों का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लिया जायजा



पटना,एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को वैशाली जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय-सह-स्मृति स्तूप परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम और 11 से 13 दिसंबर तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन-2026 की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने भगवान बुद्ध की पूजा-अर्चना कर राज्य की सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसके बाद उन्होंने परिसर में प्रस्तावित मुख्य मंच और सम्मेलन से जुड़ी अन्य तैयारियों का निरीक्षण किया। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग और बिहार हेरिटेज डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आगंतुक केंद्र में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बौद्ध देशों से आने वाले सभी प्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं एवं सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मेलन में शामिल होने के इच्छुक लोगों का आगमन सुगम बनाया जाए। उनके आवासन, भोजन, आवागमन और अन्य आवश्यक सुविधाओं का समुचित प्रबंध होना चाहिए। उन्होंने बौद्ध देशों से आने वाले प्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं को बिहार के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराने की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। इसके लिए पर्यटन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर बोधगया, राजगीर, केसरिया सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के भ्रमण की कार्ययोजना तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को बौद्ध देशों को सम्मेलन के आमंत्रण पत्र भेजने और वहां के प्रतिनिधियों एवं समन्वयकों से लगातार संपर्क बनाए रखने के लिए विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया। प्रतिनिधियों के सुगम आवागमन के लिए ई-बसों की व्यवस्था करने को भी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि श्रद्धालुओं के आवासन, आवागमन, भोजन और सुरक्षा की व्यवस्था में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अभिषेक पुष्करणी तालाब का सौंदर्यीकरण कराने और वहां विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाने का निर्देश दिया, जिससे कि परिसर में मेले जैसा माहौल विकसित किया जा सके। उन्होंने सम्मेलन में स्थानीय लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने और उनके लिए भी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने वैशाली के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को देखते हुए यहां स्थायी हेलीपैड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी महत्वपूर्ण पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों पर स्थायी हेलीपैड विकसित करने की योजना तैयार की जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु आसानी से इन स्थलों तक पहुंच सकें। सम्राट चौधरी ने परिसर तक पहुंचने वाली सड़कों को दुरुस्त करने और विशेष यातायात योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया, जिससे कि सम्मेलन के दौरान आवागमन सुचारू रहे और जाम की समस्या उत्पन्न न हो। इसके अलावा सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान के तहत आसपास के क्षेत्रों और लिंक पथों के किनारे स्थित गांवों में साफ-सफाई सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को कहा।

फिट इंडिया संडेज़ ऑन साइकिल का 100वाँ संस्करण भारत की ओलंपिक आकांक्षाओं को समर्पित

पटना,एजेंसी। फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत फिट इंडिया संडेज़ ऑन साइकिल के 100वें संस्करण का आयोजन आगामी रविवार, 29 नवंबर 2026 को देशभर में हैस टैग इंडिया रेडी 4 ओलंपिक्स थीम के साथ किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य फिटनेस, साइकिलिंग, पर्यावरण संरक्षण और खेलों में व्यापक जनभागीदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य कार्यक्रम पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। इस अवसर पर देशभर में 1.5 लाख से अधिक माई भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी अपेक्षित है तथा 600 से अधिक जिलों में साइकिल रैलियों का आयोजन किया जाएगा।

पटना में साइकिल रैली पटना में इस अवसर पर 29 नवंबर 2026 को दीघा घाट, जेपी गंगा पथ (मरीन ड्राइव), पटना में साइकिल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसका नेतृत्व डॉ. प्रमोद कुमार, मंत्री, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार करेंगे। इस अवसर पर संजीव चौरसिया, विधायक, दीघा, संजय कुमार गुप्ता,विधायक, कुम्हरार तथा बॉबी कुमार, एशियाई खेलों के कांस्य पदक विजेता सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रहेगी। इस अवसर पर मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि फिटनेस एक स्वस्थ एवं प्रगतिशील राष्ट्र की आधारशिला है। साइकिलिंग शारीरिक स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम है। फिट इंडिया संडेज़ ऑन साइकिल जैसी पहल के माध्यम से हमारा उद्देश्य



नागरिकों, विशेषकर युवाओं को फिटनेस को अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना तथा भारत की ओलंपिक आकांक्षाओं को साकार करने में योगदान देना है। संडेज़ ऑन साइकिल की शुरुआत 17 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम से प्रदूषण का समाधान' संदेश के साथ हुई थी। 100 संस्करणों की यात्रा में इस पहल के माध्यम से देशभर में लगभग 40 लाख सामूहिक प्रतिभागिताएँ दर्ज की गई हैं। वर्तमान में लगभग 10,000 स्थानों पर इसका आयोजन किया जा रहा है तथा 6,000 से अधिक फिट इंडिया नमो साइकिलिंग क्लब स्थापित किए जा चुके हैं। इस 100वें संस्करण के माध्यम से ओलंपिक के तीन मूलभूत मूल्यों उत्कृष्टता, सम्मान एवं मैत्री — को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। भारत द्वारा वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों और वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी की आकांक्षा के बीच इस प्रकार की पहल देश में जमीनी स्तर पर खेल संस्कृति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

एक नजर

महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी : जापान को 1-0 से हराकर फाइनल में पहुंचा चीन



भोपाल,एजेंसी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चल रही महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में शुक्रवार को खेले गए पहले सेमीफाइन मुकाबले में चीन ने जापान को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। मुकाबले का फैसला आखिरी मिनट में हुआ। वहीं, कोरिया ने थाईलैंड को 4-1 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में पांचवां स्थान हासिल किया। अब सभी की नजरें मेजबान और मौजूदा चैंपियन भारत के सेमीफाइनल मुकाबले पर टिकी हैं। भारतीय टीम का सामना मलेशिया से होगा। भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाम सात बजे शुरू होने वाले इस मैच में भारत की कोशिश जीत दर्ज कर फाइनल में जगह पक्की करने की होगी।

59वें मिनट में चीन ने दागा निर्णायक गोल

शुक्रवार को चीन और जापान के बीच खेला गया पहले सेमीफाइनल मुकाबला आखिरी मिनटों तक गोलरहित रहा। दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैच के 59वें मिनट में चीन की झांग हेयांग ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। यही गोल निर्णायक साबित हुआ और चीन ने फाइनल का टिकट हासिल कर लिया।

कोरिया ने थाईलैंड को 4-1 से हराया

इससे पहले पांचवें और छठे स्थान के लिए खेले गए मुकाबले में कोरिया ने थाईलैंड को 4-1 से पराजित किया। कोरिया की ओर से पार्क मिहयांग ने दो गोल किए, जबकि पार्क सेउंगए और जू सोयोन ने एक-एक गोल दागा। थाईलैंड के लिए इनपा कुंजिरा ने पेनल्टी स्ट्रोक पर एकमात्र गोल किया।

लीग मैच में भारत ने मलेशिया को दी थी शिकस्त

भारत और मलेशिया के बीच टूर्नामेंट में इससे पहले 19 नवंबर को लीग मुकाबला हुआ था। इसमें भारतीय टीम ने मलेशिया को 4-1 से हराया था। अब सेमीफाइनल में भी भारतीय खिलाड़ियों से इसी प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद होगी। हालांकि, फाइनल में पहुंचने की चुनौती के बीच मलेशिया को कम आंकना भारत के लिए भारी पड़ सकता है।

सचिवालय प्रीमियर लीग में यूनाइटेड और जायंट्स ने दर्ज की जीत



देहरादून। सचिवालय प्रीमियर लीग 2026 में शुक्रवार को खेले गए दो रोमांचक मुकाबलों में सचिवालय यूनाइटेड और सचिवालय जायंट्स ने जीत दर्ज की। पहले मुकाबले में यूनाइटेड ने सचिवालय बुल्स को 19 रनों से हराया, जबकि दूसरे मैच में सचिवालय जायंट्स ने सचिवालय डेंजर्स को छह रनों से मात दी। पहले मुकाबले में सचिवालय यूनाइटेड की टीम 16.5 ओवर में 110 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। संतोष पांडे ने सर्वाधिक 27 और प्रियांशु आहूजा ने 25 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सचिवालय बुल्स की टीम 16 ओवर में 91 रन ही बना सकी। बुल्स की ओर से राहुल जेटली ने 26 रन बनाए। यूनाइटेड के अरविंद दानू ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 22 रन देकर पांच विकेट झटके, जबकि अंकित नौटियाल ने 15 रन देकर तीन विकेट हासिल किए। अरविंद दानू को मैन ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे मुकाबले में सचिवालय जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 185 रन बनाए। प्रमोद नेगी ने 33 गेंदों में 73 रनों की आक्रामक पारी खेली, जबकि कपिल ने 44 रन का योगदान दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सचिवालय डेंजर्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट पर 179 रन ही बना सकी। डेंजर्स की ओर से अरविंद राणा ने 43 और सुंदर सिंह ने 36 रन बनाए। जायंट्स के अमित तोमर ने तीन विकेट हासिल किए। शानदार बल्लेबाजी के लिए प्रमोद नेगी को मैन ऑफ द मैच चुना गया।

जोदार के दम पर स्पेन डेविस कप के सेमीफाइनल में, ब्रिटेन से होगा मुकाबला

बोलोग्ना। राफेल जोदार ने पिछड़ने के बाद शानदार वापसी करते हुए स्पेन को ऑस्ट्रिया के खिलाफ जीत दिलाई। इस जीत के साथ स्पेन ने डेविस कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली, जहां गुरुवार को उसका मुकाबला ब्रिटेन से होगा। बोलोग्ना में खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में स्पेन ने 1-0 की बढ़त बना रखी थी। इसके बाद जोदार को ऑस्ट्रिया के यूरी रोडियोनोव के खिलाफ पहला सेट गंवाना पड़ा लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए अगले दो सेट में केवल एक गेम गंवाया और 2-6, 6-0, 6-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ स्पेन ने क्वार्टर फाइनल भी जीत लिया। 20 वर्षीय जोदार ने मैच के बाद एक आधिकारिक बयान में कहा, 'मेरे लिए यह मुकाबला काफी मुश्किल था क्योंकि किसी भी टूर्नामेंट में शुरुआती मैच आसान नहीं होते। मैं अपनी लय हासिल नहीं कर पा रहा था। दूसरे सेट की शुरुआत में मैंने बेहतर, अधिक आक्रामक और बेसलाइन से अधिक मजबूत खेलना शुरू किया। मुझे लगता है कि इसी से मुझे मुकाबले में वापसी करने में मदद मिली। इससे पहले डेनियल मेरिडा ने जोएल श्वार्जलर को 6-4, 6-4 से हराकर स्पेन को पहली जीत दिलाई थी। इस तरह मुकाबले में युगल मैच की जरूरत नहीं पड़ी और कार्लोस अल्कराज को आराम मिल गया। मेरिडा ने कहा, 'स्पेन को पहला अंक दिलाना मेरे लिए शानदार अनुभव था। मुझे लगता है कि यहां हमारी टीम अच्छी है। आज मैं अपने सर्वश्रेष्ठ स्तर पर नहीं खेल पाया लेकिन जीत हासिल करने में सफल रहा।'

मलेशिया को 6-2 से हराकर फाइनल में पहुंचा भारत, खिताब के लिए चीन से होगी भिड़ंत

भोपाल,एजेंसी। गत चैंपियन भारतीय महिला हॉकी टीम ने शानदार आक्रामक प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी भोपाल 2026 के सेमीफाइनल में मलेशिया को 6-2 से हरा दिया। शुक्रवार को नाथू बरखेड़ा स्थित अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में मिली इस जीत के साथ ही भारत ने छठी बार टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई। अब भारतीय टीम शनिवार को खिताबी मुकाबले में चीन से भिड़ेगी। अपराजित भारतीय टीम की नजरें रिकॉर्ड चौथी बार महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने पर हैं।

भारत की ओर से टूर्नामेंट की शीर्ष स्कोरर दीपिका ने दो गोल किए, जबकि मुमताज खान, नवनीत कौर, सुनेलिता टोप्पो और इशिका ने एक-एक गोल दागा। मलेशिया की ओर से नूर अजार और नूरामीराह शाकिराह जुल्किफ्ली ने एक-एक गोल किया, लेकिन वे अपनी टीम को हार से नहीं बचा सकीं। भारत ने मुकाबले की शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और विपक्षी टीम पर दबाव बनाते हुए मिडफील्ड के जरिए खेल को नियंत्रित करने की कोशिश की। हालांकि, मलेशिया ने दाएं छोर पर अच्छी रक्षात्मक स्थिति बनाए रखी और भारतीय हमलों को रोकने के लिए लगातार हस्तक्षेप किया। पहले क्वार्टर के आगे बढ़ने के साथ भारत ने आक्रमण में तेजी दिखाई और सुनेलिता ने पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। दीपिका का शुरुआती प्रयास सीधे गोल में नहीं बदल सका, लेकिन सुनेलिता ने समझदारी दिखाते हुए गेंद मुमताज के लिए छोड़ी। मुमताज ने नजदीक से गोल कर 10वें मिनट में भारत को 1-0 की बढ़त दिला दी। दूसरे



क्वार्टर में भारतीय टीम ने अपने आक्रमण की रफ्तार और बढ़ा दी। नवनीत कौर ने 18वें मिनट में शानदार व्यक्तिगत प्रयास से भारत की बढ़त दोगुनी कर दी। उन्होंने मलेशिया की दो रक्षकों को छकाने के बाद गोलकीपर को भी चकमा देकर गेंद गोलपोस्ट में पहुंचा दी।

भारतीय खिलाड़ियों ने बेहतरीन स्टिक वर्क और आपसी तालमेल से मलेशियाई रक्षापंक्ति पर दबाव बनाए रखा। दीपिका ने 25वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। मलेशिया ने 27वें मिनट में नूर अजार के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल से वापसी की कोशिश की, लेकिन भारत ने तुरंत जवाब दिया। दीपिका ने 30वें मिनट में एक और पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत की बढ़त 4-1 कर दी। इसी स्कोर के साथ मध्यांतर हुआ। तीसरे क्वार्टर में भी भारत का दबदबा जारी रहा। सुनेलिता ने 33वें मिनट में गोल कर भारत को 5-1 से आगे कर दिया। दीपिका के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए प्रयास के बाद गेंद रिबाउंड होकर आई। सुनेलिता ने पहले प्रयास में गोल करने की कोशिश की, जिसे गोलकीपर ने रोक दिया। हालांकि, उन्होंने ढीली गेंद पर नजर बनाए रखी और उसे गोलकीपर के ऊपर से उठाकर गोलपोस्ट में पहुंचा दिया। भारत ने मिडफील्ड में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। लालरेमसियामी ने गेंद को आगे बढ़ाने और आक्रमण तैयार करने में अहम भूमिका निभाई।

मार्क मार्केज लेंगे मोटोजीपी से संन्यास, वैलेंसिया ग्रां प्री होगा आखिरी मुकाबला

पेरिस,एजेंसी। स्पेन के दिग्गज राइडर और विश्व चैंपियन मार्क मार्केज मोटोजीपी से संन्यास लेने जा रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को अचानक घोषणा की कि इस सप्ताहांत होने वाली वैलेंसिया ग्रां प्री उनकी पेशेवर राइडर के रूप में आखिरी रेस होगी। उनकी टीम डुकाटी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। मार्केज ने शुक्रवार को सप्ताहांत के पहले अभ्यास सत्र की शुरुआत से कुछ मिनट पहले यह चौंकाने वाला ऐलान किया। डुकाटी टीम ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'यह आधिकारिक है। मार्क मार्केज ने मोटोजीपी से संन्यास लेने का फैसला किया है। 2026 वैलेंसिया ग्रां प्री पेशेवर राइडर और डुकाटी लेनोवो टीम के साथ उनकी आखिरी रेस होगी।

10 बार के विश्व चैंपियन मार्केज ने अपने संदेश में लिखा, 'हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस सफर का हिस्सा रहे सभी लोगों का धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसका उतना ही आनंद लिया होगा, जितना मैंने लिया। मोटोजीपी में यह मेरी आखिरी रेस होगी। हमने इतिहास रचा है। मार्केज का डुकाटी के साथ दो साल का वैध अनुबंध था, जो 2027 और 2028 सत्र तक था। 2025 में चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्होंने टीम के साथ अनुबंध बढ़ाया था। हालांकि, पिछले सप्ताहांत पुर्तगाल के पोर्टिमाओ में अपने आठवें प्रीमियर क्लास खिताब पर कब्जा करने के बाद उन्होंने भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट प्रतिबद्धता नहीं जताई थी। इसके बावजूद डुकाटी प्रबंधन ने भरोसा जताया था कि वह टीम के साथ अपना अनुबंध पूरा करेंगे। मार्केज ने अभी तक अचानक संन्यास लेने के कारणों का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, पिछले छह वर्षों में उन्हें दाहिने कंधे की दो गंभीर चोटों से जूझना पड़ा। 2020 सत्र की शुरुआत में जेरेज में हुए एक भीषण हादसे के बाद उनका करियर लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गया था। एक सप्ताह बाद उसी ट्रैक पर वापसी की कोशिश में उनकी चोट और गंभीर हो गई थी। इसके बाद चैंपियनशिप में वापसी करने के लिए मार्केज को चार सर्जरी और पांच साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। 2025 में खिताब जीतकर उन्होंने खेल इतिहास की सबसे शानदार वापसी में से एक को पूरा किया। हालांकि, पिछले साल जापान में खिताबी जीत का जश्न मनाने के महज एक सप्ताह बाद इंडोनेशियाई ग्रां प्री की शुरुआत में एक अन्य राइडर की टक्कर से वह फिर चोटिल हो गए थे।

फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 100वां संस्करण 29 नवंबर को, देशभर में जुटेंगे हजारों साइकिल प्रेमी

नई दिल्ली। फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का 100वां संस्करण 29 नवंबर को देशभर में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक आयोजन की अगुवाई केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया पुणे के पिंपरी-चिंचवड़ से करेंगे। इस दौरान करीब 50 हजार साइकिल चालक अभियान में हिस्सा लेंगे। आयोजन की थीम 'इंडिया रेडी फॉर ओलंपिक्स' रखी गई है, जिसके तहत देश में ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को मजबूत करने का संदेश दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भारत को स्वस्थ और फिट राष्ट्र बनाने के आह्वान के बाद दिसंबर 2024 में शुरू हुआ यह अभियान अब देशव्यापी जन आंदोलन बन चुका है। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में केवल 250 स्थानों और 500 प्रतिभागियों के साथ हुई थी। दो वर्षों में इस पहल से देशभर के लोग जुड़ते चले गए। संविधान दिवस की थीम पर आयोजित इसके 99वें संस्करण में देशभर के 26 हजार से अधिक स्थानों पर लाखों नागरिकों ने हिस्सा लिया था।

इस अभियान के 100वें संस्करण को ओलंपिक आंदोलन को समर्पित किया गया है। 'माय भारत' के सहयोग से देश के प्रत्येक जिले में युवा इस आयोजन का हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा देशभर के 100 प्रमुख और ऐतिहासिक स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां 100 भारतीय ओलंपियन भी साइकिल चलाकर इस पहल से जुड़ेंगे। इसका उद्देश्य भारत को अधिक स्वस्थ और फिट राष्ट्र बनाने के प्रयासों को गति देना है। इस बार का आयोजन ओलंपिक आंदोलन के मूल्यों को भी सामने रखेगा। इसमें सुशासन और ईमानदारी, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समावेशिता, खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और कल्याण के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षित खेल की स्थायी विरासत जैसे विषयों पर जोर दिया जाएगा। यह पहल खेलों के भविष्य को नैतिकता, खिलाड़ियों की आवाज और सभी के लिए समान अवसरों के आधार पर तैयार करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसमें महिलाओं और पैरा खिलाड़ियों सहित सभी वर्गों की भागीदारी को बढ़ावा देने और युवाओं को खेल तथा फिटनेस को जीवनशैली बनाने के लिए प्रेरित करने का प्रयास किया जाएगा।

क्राइस्टचर्च टेस्ट : पहले दिन न्यूजीलैंड ने 5 विकेट पर बनाए 246 रन, लैथम और ब्लंडेल के अर्धशतक

क्राइस्टचर्च,एजेंसी। आकाश दीप की शानदार गेंदबाजी के बावजूद टॉम लैथम और टॉम ब्लंडेल के अर्धशतकों की मदद से न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 246 रन बना लिए। लैथम ने शीर्ष क्रम में संयमित बल्लेबाजी करते हुए पारी की नींव रखी, जबकि दोपहर के सत्र में भारत के लगातार तीन विकेट लेने के बाद ब्लंडेल ने पारी को संभाला। ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स के बीच छठे विकेट के लिए हुई 62 रन की अटूट साझेदारी दिन की तीन अर्धशतकीय साझेदारियों में से एक रही। उतार-चढ़ाव भरे दिन के अंत में न्यूजीलैंड ने अच्छी स्थिति हासिल कर ली।

भारत के गेंदबाजी चुनने के बाद न्यूजीलैंड ने पहले घंटे में बिना विकेट गंवाए चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया। जसप्रीत बुमराह और अंशुल कंबोज ने गेंद को अच्छी स्विंग और सीम मूवमेंट दिलाई। दोनों ने कई बार बल्लेबाजों के बाहरी किनारे को छकाया। पहले बदलाव के रूप में गेंदबाजी करने आए आकाश दीप ने भी दोनों तरफ मूवमेंट हासिल कर डेवोन कॉनवे को परेशान किया। टॉम लैथम बुमराह की गेंद पर पगबाधा के फैसले से बाल-बाल बचे। उन्होंने समीक्षा ली, जिसमें गेंद ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद लेग स्टंप के बाहर पिच हुई थी। भारत ने कुछ मौके जरूर बनाए, लेकिन लाइन और लेंथ में निरंतरता की कमी के कारण उन्हें विकेट में नहीं बदल सका। आकाश दीप को लैथम का विकेट मिल सकता था, लेकिन दूसरी स्लिप में केएल राहुल ने उनका बाहरी किनारा



छोड़ दिया। दूसरी ओर, धीमी शुरुआत के बाद कॉनवे ने नियमित रूप से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना शुरू किया और सत्र आगे बढ़ने के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया। न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज अच्छी तरह जम चुके थे और बिना विकेट गंवाए लंच तक पहुंचने की स्थिति में दिख रहे थे। लेकिन लंच से ठीक पहले आखिरी गेंद पर पदार्पण कर रहे गुरनूर बराड़ ने कॉनवे को पगबाधा आउट कर दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज ने फैसले की समीक्षा ली, लेकिन गेंद ट्रैकिंग में गेंद लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से से टकराती दिखाई दी। इस तरह न्यूजीलैंड ने 26 ओवर में एक विकेट पर 77 रन बनाकर लंच किया। लंच के बाद न्यूजीलैंड ने लगातार रन बनाना जारी रखा। पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शून्य पर आउट होने वाले लैथम ने इस दौरान अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत ने लैथम के खिलाफ संभावित डीआरएस का एक मौका गंवाया। इसके अलावा जोखिम भरे एक रन के लिए दौड़े हेनरी निकोल्स को रन आउट करने का मौका भी हाथ से निकल गया। गेंद में सीम मूवमेंट जारी था और भारतीय गेंदबाज लगातार बल्लेबाजों को असहज कर रहे थे, लेकिन इन मौकों को विकेट में नहीं बदल सके। न्यूजीलैंड ने लंच के बाद का पहला घंटा बिना कोई विकेट गंवाए निकाल लिया। लंच के बाद दूसरे घंटे में भारतीय गेंदबाजों ने कहीं अधिक आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी की और आकाश दीप ने अगुआई की। दूसरे विकेट के लिए 33 रन जुड़ने के बाद आकाश दीप ने लैथम को विकेट के पीछे कैच कराकर साझेदारी तोड़ी। इसके बाद कंबोज ने निकोल्स को आउट किया, जो पुल शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाल बैठे। बंगाल के तेज गेंदबाज आकाश दीप ने फिर रचिन रवींद्र को भी विकेट के पीछे कैच कराकर पवेलियन भेज दिया। एक विकेट पर 110 रन से न्यूजीलैंड का स्कोर चार विकेट पर 110 रन हो गया। डैरिल मिचेल और टॉम ब्लंडेल ने सत्र का बाकी खेल संभाला। न्यूजीलैंड ने इस सत्र में 24 ओवर में तीन विकेट गंवाकर 54 रन बनाए। इस दौरान मिचेल पगबाधा की अपील पर भी बच गए और भारत ने एक समीक्षा गंवा दी। चाय के बाद बुमराह ने दूसरे सत्र में अपनाए गए अपने थोड़े बदले हुए रन-अप के साथ गेंदबाजी जारी रखी। उन्होंने पुल शॉट खेलने के प्रयास में मिचेल के दस्ताने से गेंद का संपर्क कराया, लेकिन ऋषभ पंत एक मुश्किल कैच नहीं पकड़ सके।

भारत बना बिम्सटेक अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियन, श्रीलंका दूसरे स्थान पर

भुवनेश्वर,एजेंसी। श्रीलंका के धावकों ने शुक्रवार को बिम्सटेक अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता के अंतिम दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए 14 में से छह स्वर्ण पदक जीते, लेकिन यह भारत को पदक तालिका में शीर्ष पर पहुंचने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं रहा। कलिंगा स्टेडियम में आयोजित पहली बिम्सटेक अंडर-23 एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भारत 22 स्वर्ण सहित कुल 47 पदकों के साथ चैंपियन बना, जबकि श्रीलंका 10 स्वर्ण सहित 38 पदक जीतकर दूसरे स्थान पर रहा। तीन दिनों तक चली प्रतियोगिता में कुल 32 स्वर्ण पदकों का फैसला हुआ। इसमें छह देशों के 200 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। श्रीलंका ने शुक्रवार को 14 स्वर्ण पदकों में से छह अपने नाम किए। विशेष रूप से ट्रैक स्पर्धाओं में उसके खिलाड़ियों का प्रदर्शन शानदार रहा। भारत ने भी अपने खाते में आठ स्वर्ण पदक जोड़कर कुल 22 स्वर्ण के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। बांग्लादेश दो रजत और आठ कांस्य सहित कुल 10 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा। नेपाल को एक कांस्य पदक मिला, जबकि भूटान और म्यांमार का खाता नहीं खुला।

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्रतियोगिता के समापन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा, 'इस तरह के आयोजन भाग लेने वाले देशों के बीच खेल संबंधों को मजबूत करते हैं, आपसी



आदान-प्रदान को बढ़ावा देते हैं और उभरते खिलाड़ियों को मूल्यवान अनुभव प्रदान करते हैं। प्रतियोगिता में भारत का शानदार प्रदर्शन हमारे युवा खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और क्षमता को दर्शाता है।' समापन समारोह में मुख्यमंत्री माझी के अलावा ओडिशा के युवा मामले एवं खेल मंत्री सूर्यबंशी सूरज, भारत सरकार के खेल सचिव हरिरंजन राव, विदेश मंत्रालय की संयुक्त सचिव अंजू रंजन तथा पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार विजेता एमडी वालसम्मा और सुधा सिंह भी मौजूद रहीं। सूर्यबंशी सूरज ने कहा, 'कलिंगा स्टेडियम में बिम्सटेक प्रतियोगिता की मेजबानी करना अंतरराष्ट्रीय खेल केंद्र के रूप में ओडिशा की पहचान को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रतियोगिता ने ओडिशा के चार खिलाड़ियों सहित हमारे युवा एथलीटों को अपनी प्रतिभा दिखाने और दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का मूल्यवान मंच भी प्रदान किया। शुक्रवार की प्रमुख स्पर्धाओं में महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में श्रीलंका की के. रिसांसा हिरुपामा ने 24.08 सेकंड के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता।

क्राइस्टचर्च टेस्ट-लंच के बाद सही लाइन-लेंथ से गेंदबाजी करने का मिला फायदा : आकाश दीप

क्राइस्टचर्च,एजेंसी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन दो विकेट लेकर भारतीय टीम को वापसी दिलाने वाले तेज गेंदबाज आकाश दीप ने कहा कि दूसरे टेस्ट के पहले दिन लंच के बाद अनुशासन और धैर्य के साथ गेंदबाजी करने से भारतीय टीम को वापसी करने में मदद मिली। हालांकि, मेजबान टीम ने 1 विकेट पर 110 रन से वापसी करते हुए दिन का खेल समाप्त होने तक पांच विकेट पर 246 रन बना लिए। आखिरी सत्र में टॉम ब्लंडेल और ग्लेन फिलिप्स ने 62 रन की अटूट साझेदारी कर न्यूजीलैंड को संभाला।

सुबह नई गेंद से भारतीय गेंदबाजों को स्विंग और सीम मूवमेंट मिली, लेकिन टीम इसका पूरा फायदा नहीं उठा सकी। कई बार गेंद का बाहरी किनारा लगा, लेकिन वह क्षेत्ररक्षकों तक नहीं पहुंचा। दो विकेट लेने वाले आकाश दीप ने माना कि भारत पहले दिन इससे बेहतर प्रदर्शन कर सकता था। हालांकि, उन्होंने कहा कि लंच के बाद विकेट लेने की जल्दबाजी करने के बजाय सही क्षेत्र में गेंदबाजी करने पर ध्यान देने की रणनीति सफल रही। आकाश दीप ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, 'पहले सत्र में गेंद में कुछ नमी थी और वह ज्यादा तेजी से बल्ले पर नहीं आ रही थी। इसलिए किनारे से लगकर निकलने वाली गेंदें क्षेत्ररक्षकों तक नहीं पहुंच रही थीं। शुरुआत में हम गेंद को कुछ ज्यादा ही स्विंग करा रहे थे। लंच के बाद हमने सही क्षेत्र में गेंदबाजी करने और धैर्य बनाए रखने पर ध्यान देने का फैसला किया। यही हमारी योजना थी और इससे हमें तीन विकेट हासिल करने में मदद मिली। कुल मिलाकर दिन अच्छा रहा, लेकिन हम इससे बेहतर कर सकते थे। हालांकि, कोई बात नहीं। आकाश दीप ने बताया कि उनका व्यक्तिगत ध्यान बल्लेबाजों को अधिक से अधिक गेंद खेलने के लिए मजबूर करने पर था। खासकर पहले दिन परिस्थितियां गेंदबाजों के अनुकूल थीं। उन्होंने कहा, 'हमें पता था कि यह पहला दिन है और गेंदबाजों को मदद मिल रही है। इसलिए हम इसका अधिक से अधिक फायदा उठाना चाहते थे। मेरा ध्यान बल्लेबाज को ज्यादा से ज्यादा गेंद खेलने के लिए मजबूर करने पर था। मैंने अपने पहले स्पेल में पांच या छह ओवर गेंदबाजी की और कोशिश की कि बल्लेबाज 80 से 90 प्रतिशत गेंदों पर शॉट खेलने के लिए मजबूर हो। एक तेज गेंदबाज के लिए इस तरह की निरंतरता बनाए रखना आसान नहीं होता, क्योंकि कभी-कभी आप स्टंप पर गेंद डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी लाइन थोड़ी भटक सकती है। आकाश दीप का मानना है कि गेंद पुरानी होने के साथ बल्लेबाजी के लिए परिस्थितियां बेहतर होती गईं। ऐसे में गेंदबाजों के सामने रन रोकने के साथ विकेट लेने की कोशिश जारी रखने की अतिरिक्त जिम्मेदारी भी थी।

एक नजर

नेपाल-भारत के बीच गैस पाइपलाइन समझौते पर काम शुरू, संयुक्त कार्यदल का गठन



काठमांडू,एजेंसी। नेपाल में पाइपलाइन सहित गैस भंडारण गृह निर्माण की योजना पर हुए समझौते के तहत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी) और नेपाल ऑयल निगम (एनओसी) के अधिकारियों को शामिल कर एक संयुक्त कार्यदल बनाया गया है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह के हाल ही में हुए भारत दौरे में हुए समझौते के तहत इस कार्यदल के गठन का निर्णय लिया गया था। नेपाल की ओर से उद्योग मंत्रालय के सह सचिव और भारत की ओर से पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेंगे। नेपाल सरकार के अधीन गैस भंडारण गृह निर्माण की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा हैदराबाद हाउस में किए जाने के बाद इस संयुक्त कार्यदल का गठन किया गया है। इसके तहत आईओसी के अधिकारियों का एनओसी की नेत्रगंज स्थित जमीन का स्थलीय निरीक्षण करने का कार्यक्रम है। निरीक्षण के बाद पाइपलाइन की संरचना, भंडारण गृह, गैस बुलेट से अनलोडिंग की क्षमता और सिलेंडरों में गैस भरने की व्यवस्था सहित विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। भारतीय अधिकारियों का अनुमान है कि पाइपलाइन और भंडारण गृह निर्माण के लिए 1052 करोड़ भारतीय रुपये की अनुमानित लागत आ सकता है। उद्योग मंत्रालय के सह सचिव नवराज घिमिरे ने दोनों देशों के संयुक्त सचिव स्तर के संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक आज शुक्रवार को होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि भारतीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तृत चर्चा होगी। घिमिरे के मुताबिक अगले एक महीने के भीतर परियोजना से जुड़े विषयों को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखा गया है।

नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करेगा टाटा पावर, ऊर्जा मंत्री विराजभक्त श्रेष्ठ से मुलाकात



काठमांडू। नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र के विकास और देश की भावी आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए भारत की टाटा पावर और नेपाल के चौधरी ग्रुप (सीजी) ने मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है। चौधरी ग्रुप के प्रबंध निदेशक निर्वाण चौधरी ने टाटा पावर के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) प्रवीर सिन्हा के साथ ऊर्जा, जलस्रोत एवं सिंचाई मंत्री विराजभक्त श्रेष्ठ से सिंहदरबार में मुलाकात की। निर्वाण चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए इस मुलाकात की जानकारी साझा की। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र के विकास को लेकर मंत्री श्रेष्ठ के ज्ञान और सहयोग के प्रति उनके सकारात्मक रुख की सराहना की। चौधरी ने कहा कि नेपाल में ऊर्जा क्षेत्र के विकास और आर्थिक वृद्धि के अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए सीजी एनर्जी और टाटा पावर प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, 'नेपाल के आगामी विकास और आर्थिक वृद्धि को ऊर्जा देने के लिए टाटा पावर और सीजी एनर्जी प्रतिबद्ध हैं। माना जा रहा है कि दोनों समूहों के बीच प्रस्तावित सहयोग से नेपाल के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, बुनियादी ढांचे के विकास और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की संभावनाओं को मजबूती मिलेगी।

पीओके के रावलकोट मेयर अब्दुल नईम खान को बताया 'राष्ट्र विरोधी', कुर्सी छीनी



मुजफ्फराबाद (पीओके)। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) की सरकार ने रावलकोट मेयर अब्दुल नईम खान को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों का हवाला देते हुए पद मुक्त कर दिया। उन्हें प्रतिबंधित संगठन ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी के कार्यकर्ता के रूप में आतंकवाद विरोधी अधिनियम (एटीए) की चौथी अनुसूची में शामिल किया गया है। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने इस क्षेत्र में अशांति फैलाने के लिए विदेशी एजेंडे पर काम करने वाले तत्वों को जिम्मेदार ठहराया है। डान की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने गुरुवार को रावलकोट के मेयर अब्दुल नईम खान को उनके पद से हटा दिया और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में नगर निगम से उनकी सदस्यता भी खत्म कर दी। स्थानीय सरकार और ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि यह कार्रवाई 'लोकल गवर्नमेंट एक्ट, 1990' की धारा 23(2) के तहत की गई है। एजेके गृह विभाग की 15 नवंबर की एक अन्य अधिसूचना के अनुसार, खान का नाम उन लोगों की सूची में शामिल है, जिन्हें आतंकवाद-रोधी अधिनियम' की धारा 16 के तहत 'चौथी अनुसूची' में रखा गया है। इस बीच पीएमएल-एन के नेतृत्व वाली पीओके सरकार ने 15 अरब रुपये की 100 दिवसीय कार्ययोजना पेश की है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन, पर्यटन और नागरिक बुनियादी ढांचे में सुधार का वादा किया गया है। इसमें कुछ दीर्घकालिक परियोजनाएं भी शामिल हैं। प्रमुख पहल में 70 मोबाइल अस्पताल इकाइयां, 75 इलेक्ट्रिक बसें और पांच 'दानिश स्कूल' शामिल हैं। प्रधानमंत्री इफ्तिखार गिलानी का कहना है कि सरकार रुके हुए 'जागरन-द्वितीय' जलविद्युत परियोजना को पूरा करने के विकल्पों पर विचार कर रही है।

बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिला गोपालगंज में ट्रेनों के बाद मोबाइल बैंक सेवा रोकी गई

ढाका,एजेंसी। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिला गोपालगंज में मोबाइल बैंकिंग सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस बीच बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) ने गोपालगंज के तुंगीपाड़ा में अपनी पेट्रोलिंग टीम पर हुए हमले को लेकर एक मामला दर्ज कराया है। इस हमले में सरकारी वाहनों को आग लगा दी गई थी। हमलावरों ने गोला-बारूद नष्ट करने के साथ उपकरणों को लूट लिया था। प्राथमिकी में 5008 लोगों को आरोपित बनाया गया है। इनमें सात नामजद हैं। केस में हसीना की पार्टी अवामी लीग से संबद्ध संगठन छात्र लीग के जिला अध्यक्ष न्यूटन मोल्ला को मुख्य आरोपित बनाया गया है।

प्रोथोम अलो, ढाका ट्रिब्यून और द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने आज सुबह यह जानकारी दी कि गोपालगंज में नौ दिन से ट्रेन सेवाएं बंद हैं। अब जिले में बुधवार रात से मोबाइल बैंकिंग सेवा भी बंद कर दी गई है। बांग्लादेश बैंक ने बताया है कि गोपालगंज में संदिग्ध लेन-देन होने के कारण ये सेवाएं बंद की गई हैं। दो मोबाइल सेवा प्रदाताओं के अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही ये सेवाएं बंद की गईं। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि पुलिस जांच में पता चला है कि हाल ही में ढाका और कई अन्य जिलों से गोपालगंज में बड़ी रकम भेजी गई है। इसी वजह से सिर्फ इस जिले में मोबाइल बैंकिंग सेवाओं को



अस्थायी रूप से बंद किया गया है। गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने खुफिया एजेंसियों का हवाला देते हुए बताया कि गिरफ्तारी से बचने के लिए अलग-अलग जिलों के लोग गोपालगंज में आकर छिप गए हैं। ऐसी जानकारी मिली थी कि उनके मोबाइल खातों में पैसे भेजे गए हैं।

रेल मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार फिलहाल ट्रेन सेवा फिर से शुरू करने पर विचार नहीं कर रही है। सूत्रों ने कहा कि स्थिति सामान्य होने पर ही इस बारे में कोई कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा जिला परिषदों, उपजिला परिषदों, नगर पालिकाओं और यूनियन परिषदों को देशभर में दी जाने वाली धनराशि की तीसरी किश्त गोपालगंज के लिए अभी जारी नहीं की जाएगी। इन संस्थाओं को आमतौर पर चार किश्तों में वित्तीय सहायता मिलती है। गोपालगंज के लिए जनवरी से मार्च तक की किश्त जारी करने पर रोक रहेगी। पुलिस ने बताया कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश की प्राथमिकी में नामजद आरोपितों में गोपालगंज जिला छात्र लीग के महासचिव अताउर रहमान पियाल, तुंगीपाड़ा उपजिला छात्र लीग के पूर्व महासचिव बाबुल हुसैन खोकोन, वर्तमान उपजिला छात्र लीग अध्यक्ष शमशुल हक, उपाध्यक्ष रिपन शेख और संयुक्त महासचिव शाहीन बिस्वास उर्फ कालू भी हैं। यह मामला 23 नवंबर को तुंगीपाड़ा थाना में दर्ज किया गया। यह शिकायत बीजीबी के खुलना सेक्टर मुख्यालय के नायब सूबेदार मो. शौकत अली ने दर्ज कराई। प्राथमिकी के अनुसार, 17 नवंबर को बीजीबी की एक टीम पुलिस, अंसार कर्मियों और कार्यकारी मजिस्ट्रेट मो. रिहाब इमाम के साथ मिलकर गोपालगंज में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिक प्रशासन की मदद कर रही थी। तुंगीपाड़ा में तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना मिलने के बाद टीम उस इलाके की ओर बढ़ी। तभी रास्ते में निलफा बाजार के पास एक समूह ने पेड़ काटकर रास्ता रोक दिया। देसी हथियारों से हमला कर दिया और क्रूड बम फोड़े। हमले के दौरान बीजीबी के एक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और एक जीप में आग लगा दी गई। हमले में नायक मो. मुनीर हुसैन, असदुज्जमां, फारूक हुसैन और असिस्टेंट डायरेक्टर मो. सैफियार रहमान गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहनों में आग लगा देने से तीन सबमशीन गन मैगजीन जल गईं। वाहनों में रखे सरकारी लैपटॉप, वॉकी-टॉकी सेट, बैटरी और चार्जर भी लूट लिए गए। कुल नुकसान का अनुमान 6.51 करोड़ टका लगाया गया है। पुलिस ने बताया कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच ढाका की एक अदालत ने हसीना के पूर्व डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी केएम सखावत मून और दो अन्य लोगों को आतंकवाद-रोधी मामले में आज जेल भेज दिया। अतिरिक्त लोक अभियोजक मेहम्मद शम्सुद दोहा सुमन ने बताया कि तीनों को कल गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार किए गए अन्य दो लोगों में मदारिपुर के पूर्व डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद इलियास हुसैन और टैक्स वकील सूफी मो. अल मामून शामिल हैं। इन पर सरकार के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाने का आरोप है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश मुख्यालय की आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार कानून-व्यवस्था बनाए रखने और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छह जिलों में 113 प्लाटून तैनात की गई है। ढाका जिले के सावर, आशुलिया में (18 प्लाटून), नारायणगंज में सात, गाजीपुर में 18, गोपालगंज में 56, चट्टोग्राम तीन और कॉक्स बाजार सात प्लाटून तैनात की गई हैं। जरूरत पड़ने पर चार और प्लाटून को स्टैंडबाय पर रखा गया है। बीजीबी जवान गृह मंत्रालय के निर्देशों के तहत और संबंधित जिला प्रशासन और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। बांग्लादेश छात्र लीग (छात्र लीग) बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी अवामी लीग का छात्र संगठन है। इसकी स्थापना शेख मुजीबुर रहमान ने 4 जनवरी, 1948 को ढाका विश्वविद्यालय में की थी। शुरुआत में इसे पूर्वी पाकिस्तान मुस्लिम छात्र लीग और बाद में पूर्वी पाकिस्तान छात्र लीग कहा जाता था। यह संगठन 1952 के भाषा आंदोलन, 1971 के मुक्ति संग्राम और 1990 के जन आंदोलन से जुड़ा रहा है। 23 अक्टूबर, 2024 को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत छात्र लीग पर प्रतिबंध लगा दिया और इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया। बाद में अवामी लीग की गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया और उसका पंजीकरण निलंबित कर दिया गया। शेख हसीना अवामी लीग की अध्यक्ष हैं।

भोटेकोशी बाढ़ में सार्वजनिक यातायात क्षेत्र के 676 लोग अब भी लापता, 140 करोड़ रुपये का नुकसान

काठमांडू। नेपाल के भोटेकोशी नदी में 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ से सार्वजनिक यातायात क्षेत्र में हुए मानवीय और भौतिक नुकसान का विवरण सार्वजनिक किया गया है। बाढ़ में सार्वजनिक यातायात क्षेत्र से जुड़े कुल 782 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें 676 लोग अब भी लापता हैं। वहीं, 39 लोगों की मौत हुई है और तीन लोग घायल हुए हैं।

यातायात क्षेत्र को हुए नुकसान के आकलन के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट भौतिक पूर्वाधार मंत्री सुनील लम्साल को सौंप दी है। रिपोर्ट में बाढ़ प्रभावित यातायात श्रमिकों, व्यवसायियों और पीड़ित परिवारों के लिए राहत, मुआवजा, सामाजिक सुरक्षा और पुनर्वास की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है। क्षति मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित 782 लोगों में 532 चालक, 111 सहचालक, 106 यात्री और 33 यातायात व्यवसायी शामिल हैं। इनमें 676 लोग लापता, 39 मृत, 64 का विवरण स्पष्ट नहीं और तीन घायल बताए गए हैं। रिपोर्ट में 14 विदेशी पर्यटकों के भी बाढ़ में लापता होने का उल्लेख है। इनमें 13 ऑस्ट्रेलियाई और एक अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। इसके अलावा, नमस्ते पासाडल्हामु यातायात प्राइवेट लिमिटेड की चार बसों में यात्रा कर रहे 103 विदेशी तीर्थयात्री भी लापता बताए गए हैं। हालांकि, इन तीर्थयात्रियों का विस्तृत व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध नहीं हो सका है। भोटेकोशी बाढ़ से सार्वजनिक यातायात क्षेत्र के कुल 409 वाहनों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 311 कंटेनर, एक ट्रेलर, नौ टिपर, 33 ट्रक, 39 बस, नौ मिनी बस और माइक्रोबस, एक मोटरसाइकिल, तीन पर्यटक चारपहिया वाहन तथा तीन सार्वजनिक जीप, वैन और सूमो शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 409 में से 384 वाहनों की अनुमानित क्षति 140 करोड़ 73 लाख 77 हजार 875 नेपाली रुपये आंकी गई है। बाकी 25 वाहनों के नुकसान का वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं हो पाया है। यातायात व्यवस्था विभाग के तत्कालीन महानिदेशक राजीव पोखरेल की अध्यक्षता में 26 भाद्र को 13 सदस्यीय क्षति मूल्यांकन समिति गठित की गई थी। समिति को 15 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि, निर्धारित समय में काम पूरा नहीं होने पर इसकी समयसीमा में 15 दिन की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई थी।

अमेरिका में तूफान से तबाही, पूर्वोत्तर और मिडवेस्ट में बाढ़, नौ लाख से अधिक घरों की बिजली गुल

वाशिंगटन (अमेरिका)। संयुक्त राज्य अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे के अवसर पर आए भीषण तूफान ने पूर्वी तट और मिडवेस्ट के कई इलाकों में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया। भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर बिजली आपूर्ति बाधित हुई। छुट्टियों के दौरान यात्रा करने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। खराब मौसम के कारण न्यूयॉर्क की मशहूर मेसीज थैंक्सगिविंग डे परेड को भी शनिवार तक के लिए टालना पड़ा।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, बिजली आपूर्ति पर नजर रखने वाली वेबसाइट 'पावरआउटेज डॉट यूएस' के अनुसार, गुरुवार शाम तक अमेरिका के मिडवेस्ट और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नौ लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के घरों की बिजली गुल रही। इनमें पेंसिल्वेनिया के दो लाख से अधिक उपभोक्ता शामिल हैं। वहीं, वर्जीनिया और मिसौरी में भी एक-एक लाख से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली संकट का सामना करना पड़ा। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट 'फ्लाइटअवेयर' के मुताबिक, गुरुवार शाम तक अमेरिका आने-जाने वाली दो हजार से अधिक उड़ानें देरी से चल रही थीं, जबकि 420 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गईं। तूफान के कारण पूर्वी तट के कई इलाकों में भारी बारिश, तेज हवाओं और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल ने बुधवार रात पूरे राज्य में आपातकाल घोषित कर दिया। न्यूयॉर्क के कुछ हिस्सों में भी गवर्नर कैथी होचुल ने आपातकाल लागू किया। मौसम एवं विज्ञान विभाग ने उत्तरी जॉर्जिया से लेकर मिड-अटलांटिक और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड



तक के क्षेत्रों में तेज हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोरान ममदानी ने गुरुवार सुबह बताया कि बाढ़ के पानी में फंसी दो कारों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना पड़ा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे पानी से भरी सड़कों पर पैदल चलने, साइकिल चलाने या वाहन ले जाने का जोखिम न उठाएं। ममदानी ने कहा, 'हम सभी को सुरक्षित रहने की याद दिलाना चाहते हैं। आपकी सुरक्षा से बढ़कर कोई मंजिल नहीं है। शहर की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के अनुसार, थैंक्सगिविंग के दिन न्यूयॉर्क में करीब डेढ़ से दो इंच बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में बारिश का आंकड़ा तीन इंच तक पहुंच गया। समुद्र में ज्वार का स्तर बढ़ने से स्टेटन आइलैंड और लॉन्ग आइलैंड समेत शहर के कई तटीय इलाकों में पानी भर गया। एजेंसी ने बताया कि सेंट्रल पार्क में हवा की रफ्तार 30 मील प्रति घंटे से अधिक रही, जबकि लागार्डिया हवाई अड्डे पर यह 56 मील प्रति घंटे तक पहुंच गई। तेज हवाओं को देखते हुए मेसीज ने अपनी वार्षिक थैंक्सगिविंग परेड शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी। आयोजकों को आशंका थी कि मैनहट्टन की ऊंची इमारतों के बीच तेज हवाओं में परेड के विशाल गुब्बारों को संभालना खतरनाक हो सकता है। परेड में हिस्सा लेने के लिए टेक्सास के पियरलैंड से न्यूयॉर्क पहुंचे एक हाईस्कूल के मार्चिंग बैंड को भी अपनी यात्रा आगे बढ़ानी पड़ी। बैंड ने बताया कि उसके करीब 500 सदस्यों के न्यूयॉर्क में दो अतिरिक्त रातें ठहरने के लिए 3.5 लाख डॉलर जुटाए गए हैं। पियरलैंड हाईस्कूल के 'प्राइड ऑफ पियरलैंड मार्चिंग बैंड' के निदेशक रयान डेमकोविच ने बताया कि यह उनके लिए बड़ी चुनौती है।

बांग्लादेश की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता मटिया बानू शुकू का निधन

ढागा (बांग्लादेश)। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता मटिया बानू शुकू नहीं रहीं। गुरुवार रात उन्हें एक निजी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट (आईसीयू) से पैलिएटिव केयर (उपशामक देखभाल) में स्थानांतरित किया गया। वहां उन्होंने गुरुवार रात लगभग 12:05 बजे अंतिम सांस ली। सांस्कृतिक कार्यकर्ता इरशादुल हक टिंकू ने उनके निधन की पुष्टि की।

ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में परिवार के सूत्रों से बताया गया कि फज्र की नमाज के बाद सुबह 5 बजे उनके पार्थिव शरीर को ढाका विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स परिसर में स्थित बकुलतला ले जाया गया। यहां सुबह 10:30 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। सुबह 11 बजे सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए उनके पार्थिव शरीर को सेंट्रल शहीद मीनार ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें ढाका विश्वविद्यालय की सेंट्रल मस्जिद ले जाया जाएगा। यहां जुमे की नमाज के बाद उनकी पहली 'नमाज-ए-जनाजा' अदा की जाएगी। इसके बाद उन्हें दफनाने के लिए उत्तरा सेक्टर 12 के कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। मटिया बानू शुकू, भाषा आंदोलन के दिग्गज अब्दुल मतीन की सबसे बड़ी बेटी और फिल्म निर्माता नूरुल आलम अतीक की पत्नी थीं। वह लंबे समय से कैंसर और किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं। 56 वर्षीय शुकू लंबे समय से



कैंसर और किडनी की जटिलताओं से जूझ रही थीं। उन्हें 2021 की फिल्म लाल मोरोगर झूटी के निर्माता के रूप में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बांग्लादेश राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इसका निर्देशन उनके पति ने किया था। यह फिल्म मुक्ति संग्राम पर केंद्रित है। उन्होंने दो दशकों से अधिक समय तक फिल्म और टेलीविजन में काम किया। उनकी चर्चित फिल्मों में लबोन्यो प्रोभा, गोल्लाछुट, टू लेट, एकता किनले अरेक्ता फ्री, जेखाने सिमांतो तोमार और प्रज्ञा परमिता शामिल हैं। शुकू ने वैकल्पिक सिनेमा और टेलीविजन नाटकों के माध्यम से बांग्लादेश के मनोरंजन जगत को एक नई दिशा दी। उन्होंने 'डूबसांतार' की पटकथा लिखी और अपने प्रोडक्शन हाउस 'पांडुलिपि कारखाना' के तहत 'मानुषेर बागान' का निर्माण किया। इस फिल्म ने मई 2026 में नई दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता। लबोन्यो प्रोभा टेलीविजन धारावाहिक है। इसकी पटकथा लेखिका के रूप में उन्हें बड़ी सफलता और पहचान

बांग्लादेश के ढाका में औद्योगिक अशांति, सावर और गाजीपुर में 300 से ज्यादा कारखाने बंद रहे

ढाका (बांग्लादेश)। राजधानी ढाका के बाहरी इलाकों में स्थित सावर और गाजीपुर औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के लगातार विरोध-प्रदर्शन और नए वेतन ढांचे की घोषणा के बावजूद कल 300 से अधिक गारमेंट कारखाने बंद रहे। गाजीपुर में गारमेंट मजदूरों ने कई जगह प्रदर्शन किया। इससे कुछ कारखानों में उत्पादन ठप हो गया। औद्योगिक जिले के अलग-अलग हिस्सों में सड़कों को जाम करने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने साउंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया।

द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बासन थाना प्रभारी हारून-उर-रशीद ने पुलिस की कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि मजदूर अधिक वेतन की मांग को लेकर कई जगहों पर सड़कों पर जमा हो गए थे। इस अशांति के कारण आने-जाने वालों को भी काफी परेशानी हुई। कई लोगों ने प्रभावित इलाकों से बचने के लिए दूसरे रास्तों का सहारा लिया। बांग्लादेश गारमेंट एंड स्वेटर वर्कर्स ट्रेड यूनियन सेंटर के महासचिव काजी रूहुल अमीन ने कहा कि नया वेतन ढांचा मजदूरों के जीवनयापन के खर्च को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वेतन तय करते समय बांग्लादेश श्रम अधिनियम, 2006 की धारा 141 में बताए गए नौ मानदंडों पर ठीक से विचार नहीं किया गया। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे मजदूरों के जीवनयापन के खर्च को ध्यान में रखते हुए वेतनमान पर फिर से विचार करें। बताया गया है कि सावर में कल सात कारखानों के मजदूरों ने काम बंद कर दिया। अशुलिया इंडस्ट्रियल पुलिस-1 के अधीक्षक मोहम्मद मोमिनुल इस्लाम भुइयां ने बताया कि अशांति के चलते 'श्रम अधिनियम' की धारा 13(1) के तहत पहले से बंद घोषित किए गए 22 कारखाने कल भी बंद रहे। इस बीच, सावर के एक गारमेंट कारखाने में तोड़फोड़, कर्मचारियों पर हमले और चोरी के आरोप में चार नामजद और 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। एकेएच स्टिच आर्ट लिमिटेड के पदाधिकारी मो. नूरुल अमीन ने सावर मॉडल पुलिस स्टेशन में यह मामला दर्ज कराया। आरोप है कि फैक्टरी में घुसने से पहले लोगों ने देसी बम फोड़े। तोड़फोड़ की। सामान लूटा। कर्मचारियों के साथ मारपीट की। पुलिस इंस्पेक्टर मोहम्मद मुर्शरफ हुसैन ने मामला दर्ज करने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान फैक्टरी के सुरक्षा गार्डों ने चार लोगों को पकड़ा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए ये चारों लोग फैक्टरी के कर्मचारी हैं। बांग्लादेश गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष महमूद हसन खान ने बताया कि अशुलिया, सावर और गाजीपुर जैसे प्रमुख कपड़ा और गारमेंट केंद्रों में अभी भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, 'कल इन इलाकों में 300 से अधिक फैक्टरियां बंद रहीं।

एक नजर

दिल्ली में बिना पासपोर्ट-वीजा रह रहा बांग्लादेशी परिवार पकड़ा गया, दो बच्चे भी शामिल

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तरी जिला पुलिस ने बाड़ा हिंदूराव इलाके से एक ही परिवार के छह सदस्यों को पकड़ा है। इनमें दो नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, जांच में सभी के बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि हुई है। उनके पास भारत में रहने के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा नहीं मिले। इसके बाद सभी को मेडिकल जांच के बाद विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) के समक्ष पेश किया गया। एफआरआरओ के आदेश पर फिलहाल सभी की आवाजाही सराय रोहिल्ला स्थित सेवा सदन तक सीमित कर दी गई है। उन्होंने बताया कि विदेशी नागरिकों के अवैध रूप से रहने की सूचना पर उत्तरी जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल, स्पेशल टास्क फोर्स और फॉरेनर्स सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम ने बाड़ा हिंदूराव स्थित सरकारी बालिका विद्यालय के पास छापा मारकर मोहम्मद जहांगीर हुसैन (50) को पकड़ा। पूछताछ में उसने खुद को बांग्लादेश का नागरिक बताया और स्वीकार किया कि वह अपने परिवार के साथ बिना वैध यात्रा एवं आव्रजन दस्तावेजों के भारत में रह रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसके परिवार के पांच अन्य सदस्यों को भी तलाश कर हिरासत में लिया। इनमें कोहिनूर (40), नूर मोहम्मद (20), आसिफ (18) और 12 व 10 साल के दो नाबालिग बच्चे शामिल हैं। पुलिस ने सभी के दस्तावेजों की जांच की। इसमें उनकी बांग्लादेशी नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मिले। जांच में यह भी सामने आया कि परिवार दिल्ली के सदर बाजार स्थित आजाद मार्केट इलाके में रह रहा था। पुलिस ने सभी छह लोगों का अरुणा आसफ अली अस्पताल में मेडिकल कराया। इसके बाद 26 नवंबर को उन्हें दिल्ली के एफआरआरओ के समक्ष पेश किया गया। नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों और पुलिस की रिपोर्ट की जांच के बाद एफआरआरओ ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 के प्रावधानों के तहत प्रतिबंध आदेश जारी किया। इसके तहत आगे की कार्रवाई होने तक सभी छह लोगों की आवाजाही सराय रोहिल्ला के शाहजादा बाग स्थित सेवा सदन तक सीमित कर दी गई है। पुलिस के मुताबिक, परिवार का स्थायी पता बांग्लादेश के नारायणगंज जिले के सोनारगांव थाना क्षेत्र के त्रिपुरदी गांव का दर्ज है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि खुफिया सूचना के आधार पर तीन इकाइयों ने समन्वित कार्रवाई की। सत्यापन के बाद मामले को आगे की कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा गया है।

'भारत समिट' में 'वोट चोर गद्दी छोड़' वीडियो हटाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने हैदराबाद में भारत समिट-2026 के दौरान इटली की 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' (पीईएस) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने मंच से कथित तौर पर 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाने वाले वीडियो को हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दिया है। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया। यह याचिका वकील जाहिद अली ने दायर की थी। याचिका में घटनाक्रम की एसआईटी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई थी। याचिका मेंआरोप लगाया गया था कि 13 और 14 नवंबर को तेलंगाना सरकार की मेजबानी में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के मंच से भारत की घरेलू राजनीति में सीधा हस्तक्षेप किया गया है। याचिका में कहा गया था कि समिट के दौरान इटली की 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' (पीईएस) के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक ने मंच से कथित तौर पर 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया। याचिकाकर्ता का दावा था कि विदेशी प्रतिनिधि ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राजनीतिक अभियान का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया, जो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाहरी दखल के समान है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत की निगरानी में एक स्वतंत्र एसआईटी का गठन करने की मांग की थी, जो समिट के आयोजन, आयोजकों की भूमिका और विदेशी मेहमानों को दी गई सरकारी मंजूरियों की गहन जांच करे। यह पता लगाया जाए कि क्या विदेशी प्रतिनिधियों ने अपने भारतदौरे के उद्देश्य और वीजा नियमों का उल्लंघन कर राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया है।

वडोदरा के पास एके-47 के साथ जैश-ए-मोहम्मद का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार

वडोदरा,एजेंसी। गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) ने आतंकी हमले की साजिश रचने के आरोप में जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। उसे हालोल-वडोदरा हाईवे पर गोल्डन चौकड़ी के पास से पकड़ा गया। उसके कब्जे से एक एके-47 राइफल और 23 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार, आरोपित वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने के इरादे से आया था। आरोपित की पहचान असम के करीमगंज जिले के मूल निवासी मोहम्मद शाहरुख इस्लाम कबीरूद्दीन के रूप में हुई है। उसके मदरसे में पढ़ाई करने की जानकारी भी सामने आई है। प्रारंभिक जांच के मुताबिक, वह असम से ट्रेन के जरिए भोपाल और फिर वहां से बस से वडोदरा पहुंचा था।



गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय को मिली सूचना के आधार पर विभिन्न टीमें सक्रिय की गईं। आरोपित के सयाजीगंज रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल मिलन में ठहरे होने की जानकारी मिलने पर टीम वहां पहुंची, लेकिन वह बिना चेक-आउट किए फरार हो चुका था। इसके बाद दाहोद से वडोदरा लौटते समय हालोल-वडोदरा रोड पर नाकाबंदी कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपित पिछले एक वर्ष से पाकिस्तान स्थित जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर मुफ्ती रफीक उर्फ 'इब्न अब्दुल्ला' के संपर्क में था। हैंडलर के निर्देश पर उसने वडोदरा एयरफोर्स स्टेशन के गेट की रेकी की और अगले दिन दाहोद जाकर हथियार हासिल किया। उसके मोबाइल के व्हाट्सएप और गैलरी की जांच में एयरफोर्स स्टेशन के गेट के फोटो और वीडियो के साथ एके-47 जैसी असॉल्ट राइफल चलाने के प्रशिक्षण से जुड़े वीडियो भी मिले हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि हैंडलर ने नया फोन खरीदने के लिए उसे 50 हजार रुपये नकद दिए थे। वारदात के बाद आरोपित के पाकिस्तान जाकर संगठन में शामिल होने और आत्मघाती हमले को अंजाम देने की योजना होने की बात भी जांच में सामने आई है। इस मामले में एटीएस के डीआईजी सुनील जोशी ने कहा, 'आतंकी को पैसा मिला है, वह किस तरीके से मिला है और यहां उसे किसी ने मदद की है या नहीं, इस दिशा में जांच चल रही है। गिरफ्तारी के बाद एटीएस की टीमें गिरफ्तारी स्थल, संबंधित होटल और असम के करीमगंज जिले स्थित आरोपित के घर समेत विभिन्न स्थानों पर तलाशी और जांच कर रही हैं।

मोहन भागवत ने शाहनवाज हुसैन के आवास पहुंचकर बेटे-बहू को दिया आशीर्वाद



नई दिल्ली,एजेंसी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत शुक्रवार को भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन के दिल्ली स्थित आवास पहुंचे और उनके बेटे अरबाज हुसैन और पुत्रवधू अफशां को आशीर्वाद दिया।

शाहनवाज हुसैन ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, 'आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्रद्धेय मोहन भागवत जी हमारे दिल्ली स्थित आवास पर पुत्र अरबाज एवं पुत्रवधू अफशां को आशीर्वाद देने पधारे। उन्होंने कहा कि डॉ. भागवत का स्नेह और आशीर्वाद उनके पूरे परिवार के लिए अमूल्य है। शाहनवाज हुसैन ने अपने परिवार की ओर से भागवत का हृदय से आभार भी व्यक्त किया। शाहनवाज हुसैन की ओर से साझा की गई चार तस्वीरों में मोहन भागवत परिवार के सदस्यों के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में वह नवदंपति को फूलों का गुलदस्ता और उपहार देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उल्लेखनीय है कि शाहनवाज हुसैन के बेटे अरबाज का विवाह अक्टूबर में अफशां अकरम खान के साथ हुआ था।

जब सनातन मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, सनातन व भारत अलग-अलग नहीं-योगी

लखनऊ,एजेंसी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को बलरामपुर पहुंचे। यहां उन्होंने देवीपाटन मंदिर में आयोजित ब्रह्मलीन महंत महेंद्रनाथ योगी के 26वी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि भारत और सनातन को अलग नहीं किया जा सकता। सनातन मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'नेशन फर्स्ट' का नारा दिया है। राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए और इसके लिए प्रत्येक नागरिक को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि किसान ईमानदारी से खेती करे, व्यापारी ईमानदारी से अपना व्यवसाय करे और समाज के प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति पूरी निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करे। तभी राष्ट्र मजबूत होगा। परिणाम भाषणों से नहीं, बल्कि पुरुषार्थ से आते हैं।

ब्रह्मलीन महंत महेंद्र नाथ योगी का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देवीपाटन शक्तिपीठ के विकास के लिए अनेक कार्य किए। सदियों से यह शक्तिपीठ समाज को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ब्रह्मलीन महंत गोरखपुर से यहां आए थे। वहां जो भी विकास कार्य और व्यवस्थाएं देखते थे, उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार देवीपाटन में भी लागू करने का प्रयास करते थे। थारू जनजाति के विकास के लिए उनके द्वारा शुरू किया गया थारू छात्रावास आज भी सैकड़ों थारू बच्चों को निशुल्क शिक्षा और भोजन उपलब्ध करा रहा है। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए धर्मशाला का विस्तार भी उनके प्रयासों का परिणाम है। देवीपाटन शक्तिपीठ में विकास के रूप में उनके कार्य आज भी दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलीन महंत ने गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवैद्यनाथ से जो कुछ सीखा, उसे अपने कार्यों में उतारने का प्रयास किया।

रामायण के प्रसंग का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने सीता की खोज के दौरान हनुमान जी और मैनाक पर्वत के संवाद का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि जब मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को विश्राम करने के लिए कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, 'राम काजु कीन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम।' मुख्यमंत्री ने कहा कि हनुमान चालीसा और बजरंगबली के प्रति श्रद्धा प्रत्येक सनातनी के जीवन में विशेष स्थान रखती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने बड़ों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। संतों, महापुरुषों और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जीवन प्रत्येक देशवासी के लिए प्रेरणास्रोत होना चाहिए। उन्होंने युवा पीढ़ी से संतों के आदर्शों को अपने जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। कहा कि संतों की शिक्षाएं समाज को सही दिशा देने के साथ ही राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत करती हैं।

केजरीवाल का 'शीश महल' खुला, महंगे फर्नीचर कीमत के साथ प्रदर्शित

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व सरकारी आवास 'शीश महल' को शुक्रवार को मीडिया के लिए खोला है। 'शीश महल' में रखे महंगे फर्नीचर को उनकी कीमत के साथ प्रदर्शित किया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक बयान जारी करते हुए 'शीश महल' को लेकर कहा कि दिल्ली की जनता के बाद अब पंजाब की जनता को भी देखना चाहिए कि किस तरह जनता की खून-पसीने की कमाई से आलीशान शीशमहल बनाया गया। उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब की जनता के सामने इस पूरे मामले की सच्चाई आनी चाहिए।

दिल्ली के लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने पत्रकारों से कहा कि दिल्ली की जनता का पैसा, यानी टैक्स देने वालों का पैसा कहां और कितना खर्च किया गया, इसका पूरा हिसाब हर सरकार को देना चाहिए। जनता को यह जानने का अधिकार है कि दिल्ली के विकास पर खर्च होने वाला उसका पैसा पिछले मुख्यमंत्री ने किस तरह का फर्नीचर खरीदने में खर्च किया। यहां हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। यहां लिखी गई हर रकम के साथ हमने उसका बिल नंबर और इनवॉइस नंबर भी दिया है। यह पूरा घर पहले जैसा ही है, इसमें किसी भी सामान को इधर-उधर नहीं किया गया है। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसका पैसा कहां खर्च किया गया।

दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने 'शीश महल' में पत्रकारों से कहा कि आज आपके कैमरों के जरिए पूरा देश देखेगा कि दिल्ली की जनता के पैसे को कैसे बर्बाद और लूटा गया। मैं चाहता हूं कि पूरा देश आपके कैमरों के जरिए देखे कि करोड़ों रुपए का



सामान खरीदा गया है और दुनिया भर के देशों से चीजें मंगवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब जनता ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही थी तब केजरीवाल करोड़ों के शीश महल का निर्माण कर रहा था। मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली की जनता के पैसों को लूटकर शीशमहल में विदेशों से करोड़ों का सामान ला कर अय्याशी के लिए लगाया गया, जो आदमी कहता था मैं एक कमरे के घर में रहूंगा उस आदमी ने दुनिया के तमाम देशों से लाकर करोड़ों का सामान रखा है और जनता के टैक्स के पैसों से कैसे अय्याशी की गई इसका सबूत पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि 'शीश महल' में लाखों की चिमनी इटली से आई है, क्रॉकरी 31 लाख रुपये की दुनिया के अलग-अलग देशों से मंगाई गई है, फ्रिज में इंटरनेट व टीवी लगा हुआ है...कोरोना काल में यह पाप केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ किया था।

मध्य प्रदेश सरकार फिर बाजार से लेगी 1500 करोड़ रुपये का ऋण

भोपाल,एजेंसी। मध्य प्रदेश सरकार राजकोषीय अनुशासन और विकास के बीच संतुलन साधते हुए प्रदेश की आर्थिक एवं अधोसंरचनात्मक क्षमता को बेहतर करने के लिए पूंजीगत निवेश बढ़ा रही है। इसी रणनीति के तहत राज्य सरकार एक दिसंबर को 1500 करोड़ रुपये का बाजार ऋण लेगी। वित्त विभाग द्वारा शुक्रवार को जानकारी दी गई कि भारतीय रिजर्व बैंक की बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी (बीआईएस) के अंतर्गत लिया जाने वाला यह ऋण केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उधारी सीमा के भीतर है। सरकार का विशेष जोर सड़क, सिंचाई, ऊर्जा और अन्य दीर्घकालिक उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण पर है। विकासोन्मुख वित्तीय नीति के चलते वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रदेश का पूंजीगत परिव्यय एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार करने की संभावना है।

बताया गया कि समयबद्ध ऋण पुनर्भुगतान और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ राज्य सरकार प्रदेश की उत्पादन क्षमता, रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास को नई गति देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। जनसम्पर्क अधिकारी संतोष मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा एक दिसंबर को प्रस्तावित 1500 करोड़ रुपये का बाजार ऋण तीन अलग-अलग हिस्सों में 500,500 एवं 500 करोड़ रुपये के रूप में लिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदेश की कुल उधारी सीमा लगभग 87 हजार करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसमें प्रथम नौ माह के लिए 58 हजार 274 करोड़ रुपये की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत



है। माह नवंबर तक राज्य सरकार 51 हजार 900 करोड़ रुपये का बाजार ऋण प्राप्त कर चुकी है। प्रस्तावित ऋण भी निर्धारित सीमा के भीतर है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने ऋण पुनर्भुगतान में वित्तीय अनुशासन का बेहतर रिकॉर्ड कायम रखा है। राज्य सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 29 हजार 980 करोड़ रुपये तथा चालू वित्तीय वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15 हजार 573 करोड़ रुपये का ऋण पुनर्भुगतान किया है। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश सरकार ने अपने ऋण दायित्वों के भुगतान में कभी डिफॉल्ट नहीं किया है। सभी निर्धारित भुगतान समय पर किए गए हैं। यह राज्य की ऋण प्रबंधन क्षमता और वित्तीय विश्वसनीयता को दर्शाता है। वित्त विभाग के मुताबिक, प्रदेश में अधोसंरचना विकास को नई गति देने के लिए पूंजीगत निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य का पूंजीगत परिव्यय एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार करने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त ऋण का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई परियोजनाओं, सड़क एवं एक्सप्रेस-वे, विद्युत अधोसंरचना तथा अन्य दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए किया जाता है। इन परियोजनाओं से कृषि उत्पादन, औद्योगिक गतिविधियों, व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। राज्य सरकार के अनुसार वेतन-भत्ते, पेंशन, अनुदान तथा लाड़ली बहना और मुख्यमंत्री किसान कल्याण जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के राजस्व व्यय की पूर्ति के लिए ऋण नहीं लिया जाता। ऋण प्रबंधन में उत्पादक पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता दी जाती है। मध्य प्रदेश सरकार संविधान के अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उधारी सीमा और राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (एफआरबीएम) के प्रावधानों के अनुरूप ऋण प्राप्त कर रही है। बजट अनुमान 2026-27 में राज्य का ऋण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का अनुपात 32.53 प्रतिशत अनुमानित है। प्रदेश में ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात लगभग 10 से 11 प्रतिशत है। यह राज्य की राजस्व प्राप्तियों के मुकाबले ब्याज भुगतान के नियंत्रित स्तर को दर्शाता है। वहीं, पिछले दस वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी 10 प्रतिशत से ऊपर रही है। राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित तिमाही कैलेंडर के अनुसार योजनाबद्ध तरीके से बाजार ऋण प्राप्त कर रही है, जिससे ऋण प्रबंधन में पारदर्शिता और बेहतर ब्याज दरों का लाभ मिल रहा है। सार्वजनिक ऋण के आंकलन में केवल प्रति व्यक्ति ऋण को आधार बनाना राज्य की वास्तविक आर्थिक स्थिति का संपूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं करता। ऋण का मूल्यांकन राज्य की जीएसडीपी, राजस्व प्राप्तियों, ब्याज भुगतान क्षमता, पुनर्भुगतान रिकॉर्ड और ऋण से निर्मित उत्पादक परिसंपत्तियों के आधार पर किया जाना आवश्यक है।

वर्ष 2050 तक झारखंड को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने का लें संकल्प : राज्यपाल

रांची,एजेंसी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास राज्य के भविष्य को मजबूत बनाने के प्रमुख आधार हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगारपरक प्रशिक्षण और ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों तक बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना आवश्यक है। राज्यपाल शुक्रवार को रांची के एक होटल में आयोजित 'झारखंड चर्चा 2026' को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए उनके प्रभावी क्रियान्वयन, स्थानीय समुदायों की भागीदारी और नियमित मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड का गठन वर्ष 2000 में हुआ था। अब गहन आत्ममंथन करते हुए वर्ष 2050 तक राज्य को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का संकल्प लेना चाहिए। इसके लिए विकास का स्पष्ट एवं व्यावहारिक रोडमैप तैयार कर राज्य सरकार को सुझाव देना चाहिए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार, निजी क्षेत्र,



सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को मिलकर सभी क्षेत्रों में संतुलित, समावेशी और सतत विकास के लिए प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में झारखंड की महत्वपूर्ण भूमिका है।

प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध खनिज एवं वन संपदा और गौरवशाली जनजातीय संस्कृति से संपन्न इस राज्य में विकास की व्यापक संभावनाएं हैं। जरूरत उपलब्ध संसाधनों, स्थानीय कौशल और प्रतिभा का बेहतर उपयोग कर इन संभावनाओं को उपलब्धियों में बदलने की है। राज्यपाल ने कहा कि निवेश, आधुनिक तकनीक और नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ उद्योगों का विकास तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है। पर्यटन के क्षेत्र में जलप्रपातों, पहाड़ियों, वन क्षेत्रों, जनजातीय जीवनशैली, पारंपरिक कला और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर रोजगार एवं आय के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना समग्र विकास की महत्वपूर्ण शर्त है। कृषि एवं पशुपालन, वन आधारित उत्पाद, हस्तशिल्प और छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित कर ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाई जा सकती है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)